

श्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

मं० 37]

् नई दिल्ला, शनियार, सि..म्बर 11, 1971/भार 20, 1893

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11, 1971 BHADRA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II---खण्ड 3---इव्खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों श्रीर (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक ग्राहेश श्रीर श्रधिसूबनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi, the 25th May 1971

S.O. 3341.—Consequent on his reversion to the Central Water and Power Commission (Power Wing), Shri S. L. Jain relinquished charge of the post of Assistant Director in the Northern Regional Electricity Board, New Delhi, on the afternoon of the 13th May, 1971.

[No. 21/1/68-Adm.I(PW)

केरीय बिजली प्राधिक एग

नई दिल्ली 25 मई, 1971

एस० ग्रो॰ 3341.—केन्द्रीय जल ग्रीर विद्युत् श्रायोग (विद्युत् स्कंध) को उनके प्रत्यावर्तन के फलस्वरप, श्री एस० एल० जैन ने 13 मई, 1971 के श्रपराह्म से उत्तर क्षेत्रीय विश्वत्-मंडल, नई दिल्ली में महायक निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

[संःथा 21/1/68-प्रशा-1 (वि० स्कं०]

New Delhi, the 9th June 1971

S.O. 3342.—Consequent on his reversion from deputation, Shri L. P. Jain, relinquished charge of the post of Secretary, on the forenoon of 17th May, 1971, in the North-Eastern Regional Electricity Board, Shillong.

[No. 21/4/67-Adm.I(PW).]

नई दिल्यों ५ जून, 1971

एस० भ्राः 3342.—प्रतिनियुवित से उनके प्रत्यावर्तन के फलसारूप, श्रो एल० पी० जैन ने 17 मई, 1971 के पूर्वाह्म से उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विद्युन्-मडल, शिलांग में सिचव के पद का कार्यभार त्याग दिया।

S.O. 3343.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 6 of the Section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948, the Central Electricity Authority hereby appoints Shri I. K. Ahluwalia. Assistant Director. Central Water and Power Commission (Power Wing), as Secretary, North-Eastern Regional Electricity Board, Shillon, with effect from the forenoon of the 17th May, 1971, until further orders.

[No. 20/3/70-Adm.I(PW).]

S. S. RANDHAWA, Under Secy.

for Chairman, CEA.

एस० म्रो० 3343.— विद्युत् (प्रदाय) श्रिधिनियम, 1948 के खंड 3 के उप खंड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री श्राई० के० श्राहालूवालिया, सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल श्रीर विद्युत् श्रायोग (विद्युत् स्कंध) को 17 मई, 1971 के पूर्वीह्म से, श्राने श्रादेश तक, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विद्युत्-मंडल के सचित्र के रूप में नियुक्त करता है।

ं[संख्या 2 0 ∕ 3 ∕7 0—प्रणा∘ (वि० स्कं०)]

सोहन सिंह रंधावा

बृते श्रध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Road Wing)

New Delhi, the 21st July 1971

S.O. 3344—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highways specified in the Table below to be national Highways:

TABLE
[Supplement to schedule to the National Highways Act, 156 (No. 48 of 1956]

Serial No.	National Highway	No.	Descripton of National Highways	
5A	4A		Tae Highway connecting Belgaum Anmoi, and Panaji.	Ponda
бA	5A		The Highway starting from its junction near Harwith N.H. No. 5 and terminating at the Parad	

S.No.	National Highway No.	Description of National Highways
13D	21	The highway starting fro m its junction near Chandigarh with the N.H. No. 22 and connecting Rupar, Bilaspur, Mandi. Kulu and Manali.
27A	36	The highway connecting Nowgong Dabaka and Dimapur (Manipur Road).
33A	44	The highway connecting Shillong, Passi, Badarpur and Agartala.

[No. F. PL-5(17)/69.] P.H. TRIVEDI, Dy. secy.

ने बहुन स्था परिवहम संजालय

(सद्कापभा)

नइ दिल्ली, 21 जुलाई, 1971

का० ग्रा० 3344.—राष्ट्रीय राजमाग श्रधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निम्न सारणी में उल्लिखित राजमार्गी को एत्द्वारा राष्ट्रीय राजमाग घोषित करती है:

सारणी [राष्ट्रीय राजमार्ग श्रिधिनियम, 1956 (1956की स० 48) की श्रनुसूची का श्रनुषूरक]

ऋम संरूया	राष्ट्रीय राजग् संख्मा	रार्ष राष्ट्रीय राजमार्गं का विवरण
5वत	 4क	वेलगांव, म्रनमोद पोंडा भ्रौर पानाजी को जोड़ने वाला राजमार्ग ।
6क	5軒	राष्ट्रीय राजमार्ग स० 5 के साथ के हरिदासपुर के पास के श्रपने जक्शन से प्रारम्भ होने वाजा श्रौर पारादीप पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
1 3घ	21	राष्ट्रीय राजमार्ग स० 22 के साथ के चढ़ीगड़ के पास के अपने जंकणन से प्रारम्भ होने वाला और रोपड़, विलासपुर, मंड़ी, कुलू और मनाली को जोड़ने वाला राजमार्ग।
2 7क	36	नौगांव दबका भ्रौर दीमापुर(मणिपुर सड़क) को जोड़ने वाला राजमार्ग ।
3 3क	44	शीसांग, पासी, बदरपुर श्रौर अगरताला को जोड़ने वासा राजमार्ग ।

[सं० पी० एल०-5 (17)/69]

पी० एच० तिवेदी, अप-सचित्र

(Director General of Shipping)

MERCHANT SHIPPING

Bombay, the 20th August 1971

S.O. 3345.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with the order of the Government of India in the late Ministry of Transport & Communications No. S.O. 771 dated the 7th Mærch, 1962 and in supercession of the Notification No. S.O. 3828 dated the 8th September, 1970, the Director General of Shipping hereby appoints Shri S.K. Berry, Engineer & Ship Surveyor, as the officer who shall be incharge of the office of the Merchantile Marine Department at the port of Marmugao, until further orders.

This notification shall be deemed to have come into force on the 13th day of July 1971.

[No. 130-SH(52)/61.] R. DORISWAMY, Director General of Shipping.

(नौबहन महा निवेशालय)

व्यापारिक नौबहन

बम्बई, 20 श्रगस्त, 1971

का श्रा ० 3345. — भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय स०का ० आ ० 771 दिनांक 7 मार्च, 1962 के साथ पठित व्यापारिक नौवहन ग्रिधिनियम 1958 (1958 के 44) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा ग्रिधिसूचना सं० का० आ ० 3828 दिनांक 8 सितंबर 1970 के श्रिधिक्रमण में नौवहन महा निदेशक एतद्द्वारा इस श्रिधसूचना के साथ श्री एस ० के ० बेरी, श्रिभियन्ता तथा पोत सर्वेक्षक को धगले श्रादेश होने तक मारमुगांव पत्तन पर जल परिवहन विभाग के कार्यालय श्रीधकारी नियुक्त करते हैं:

यह प्रधिसूचना जुलाई, 1971 के 13वें दिनांक से लागू समझा जाएगा।

[सं ० मि० 132-एस ०एच ०(52)/61] ग्रार ० दोरायस्थामी, नौबहन महा निदेशक ।

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 10th June 1971

8.0. 3346.—Whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Zonal Development plan of Zone D-5 (D.I.Z. Gole Market area) as regards the areas mentioned in the Schedule hereto annexed, in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act inviting objections and suggestions;

And, whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the areas mentioned in the aforesaid Schedule, have decided to modify the zonal development plan of zone D-5 (D.I.Z. Gole Market area):

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the sald Act hereby makes the following modifications in the said zonal development plan namely:—

"Land use of a 0.278 hectare (approximately) plot bounded by 45.72 meter wide Irwin Road on the south-east, 18.288 meter wide proposed road

on the south-west, Higher Secondary School in the north-west and general business and commerce on the north-east to be changed from "residential" to "commercial".

THE SCHEDULE

Land use of a 0.278 hectare (approximately) plot bounded by 45.72 meter wide Irwin Road on the south-east, 18.288 meter wide proposed road on the south-west, Higher Secondary School in the north-west and general business and commerce on the north-east.

[Case No. 21017(13)/68-UDI.]

निर्माण भीर भावास मंत्रासय

नई दिल्ली, 10 जून, 1971

एस० ग्रो० 3346.—यतः दिल्ली विकास श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि उक्त श्रिधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है, ग्रापत्तियों तथा धूसावों को श्रामंत्रित करते हुए, एतद्पावद्व श्रनुसूची में उिल्लिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र डी० 5, की क्षेत्रीय विकास योजना (डी० श्राई० जेंड़ गोल माक्ष्ट क्षेत्र) में केन्दीय सरकार ने कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया था;

ता यतः केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त श्रनुत्वो में उत्लिखित क्षेत्रो के सम्बन्ध में धाप-तियां तथा सूझावों पर विधार करने के पश्चात, डील्5, क्षेत्र (डी० ग्राई० जेड गोल मार्कीट) की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है;

त्रतएब, ग्रव केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिष्ठितियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा श्रदत्त शिक्तवीं का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :----

> "दक्षिग-पूर्व में 45.72 मीटर चौड़ी इकिंत रोड, दक्षिग-पश्चिम में 18.288 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क, उत्तर-पश्चिम में हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा उत्तर-पूर्व में सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य से घिरा हुन्ना लगभग 0.278 हेक्टर के एक प्लाट का भु-उपयोग "रिहायशी" से बदल कर "व्यापारिक" किया जाना है"

श्रनु रूची

विक्षण-पूर्व में 45.72 मीटर चौड़ी इर्विन रोड से, दक्षिण-पश्चिम में 18.288 मीटर चौड़ो प्रस्तावित सड़क, उत्तर-पश्चिम में हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा उत्तर-पूर्व में सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य से घिरा हुआ लगभग 0.278 हेक्टर के एक प्लाट का भू-उपयोग

किस नं० 21017 (13)/68-पृडी-I.]

New Delhi, the 20th August 1971

S.O. 3347.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri M. W. K. Yusufzai, President of the New Delhi Municipal Committee, as a member of the Develi Development Authority in place of Shri S. C. Chhabra and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-LSG dated the 30th December, 1957, namely:—

In the said notification, in item 10, for the entry "Shri S. C. Chhabra" the following entry shall be substituted, namely:—

"M. W. K. Yusufzai".

[No. 5-2/69-UDI.]

नई दिल्ली, 20 ग्रगस्त, 1971

एस० श्रो० 3347. — दिल्ली विकास श्रधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 का उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के संग पढ़ी जाने वाली उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत्द्द्वारा, नई दिल्ली नगर पालिका के श्रध्यक्ष श्री एम०, डब्ल्यू० के० युसुफजाई को श्री एस० सी० छाबड़ा के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के छप में नियुक्त करती है, तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंतालय के दिनाक 30, दिसम्बर, 1957 की श्रधिमूचना सं० 12-173/57-एस० एस० जी० में निम्नलिखित श्रीर संशोधन करती है, नामत:—

उक्त ग्रिधिसूचना की मद 10 में 'श्री एस० सी० छाबड़ा' के इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:—

"एम० डब्ल्यू० के० युसुफजाई "

[सं० 5-2/69-यू० डो० I]

एल० एम० सुखवाणी, श्रवर सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 6th September 1971

S.O. 3348.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Devxelopment and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rule 8 of the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri (V. K. Shah, to be member of the Central Advisory Council of Industries till the 4th March, 1972, in place of Shri Chandra-Kant S. Desai, and directs that the following amendment shall be made in the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 971 dated the 5th March, 1970 as amended vide No. S.O. 1367 dated the 9th April, 1970, namely:

In the said order, for the entry No. 5 relating to Shri Chandrakant S. Desai, the following shall be substituted:

"5. Shri V K, Shah, President, National Alliance of Young Entrepreneurs, Alliance House, C-20/B, Green Park Extension, New Delhi-16."

[No. 1(3)/Lic. Pol./69.]

R K CHADHA, Under Secy...

श्रीकोगिक विकास मंत्रालय

ग्रादेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1971

का० ग्रा॰ 3348.—-ग्राई० डी० ग्रार० ए०/517.—-उद्योग (विकास तथा विनियमन, ग्राधिनियम) 1951 (1951का 65)को घारा 5 के बारा प्रदत्त शक्तियाँका प्रयोगकरते हुए, एवम् केन्द्रीय सलाहकार परिषद (कार्यावि) नियम, 1952 व नियम 8 व साथ पढते हुए, वे द्वीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० के० शाह को श्री चन्द्रकान्त एम० देसाई वे स्थान पर 4 मार्च, 1972 तक के लिये उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आतरिक व्यापार तथा समवाय-वार्य-मत्न.लय (श्रीद्योगिक विकास विभाग) के श्रादेश स०का० श्रा० 97 दिनाक 5 मार्च, 1970 जिसे स०का० श्रा० 1367 दिनाक 9 श्रप्रैल, 1970 के हारासशोधित किया गया, के निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, श्रथ तः - —

जयत्त ग्रादेश में, श्री चन्द्रकान्तु एस० देसाई से संबंधित प्रविधिट सं० 5 के ॄ्रियान पर सिम्स-लिकित को रखा जाएगा,

> " श्री बी० वें० माह, ग्रध्यक्ष, नेशनल एलायेन ग्राफयग इटरप्रेन्योस, सिलयंस हाउस,सी०-20/बी, ग्रीन पार्क एक्सटैन्सन, नई दिल्ली-16

> > [स॰ 1(3)/एल॰पी॰/69]

ग्रार० के० चड्डा, ग्रवर सचिव।

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 14th July 1971

S.O. 3349 —In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eighteen licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted authorizing the licensees to use the Standard Marks:

THE SCHEDULE

	THE OCHEDOLE						
Sl. No.	Licence No. (CM, L—)			Name and Address of the Licensee	Article Process covered by the Licence and the Relevant IS: Designation		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
I	CM/L-2401 1-9-1970	1-9-1970	31-8-1971	Andhra Steel Corporation Ltd., Malkapuram, Visa hapatnam Port, Andhra Pradesh (Office: Thompson Street, Visakhapatnam, Andhra Pradesh)	Co'd twisted deformed steel bars—IS: 1786 1966		
2	CM/L-2402 3-9-1970	16- 9- 1970	15-9-1971	Krishna Engineering Industries, New Chha cthrauli Road, Jagadhri (Haryana)	Rolled brass plate, Cuzn 37—IS: 410-1967		
3	CM/L-2403 9-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	Mysore Cements Ltd., Adityapatna, Ammasandra P.O., Tumkur Distt., Mysore State [Office: 1, Vidhana Veedhi, Coffee Board Building (4th Floor), Bangalore-1]	Ordinary portland cement—IS: 269-196		
4	CM/L-2404 10-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	Regal Products Private Ltd., 186, Royapettah High Road, Royapettah, Madras-14	Dye based fountain pen ink, blue—IS: 1221-1957		
5	CM/L-2405 11-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Bharat Pulverising Mills Private Ltd 1074, Thiruvottiyur High Road, Madras-19	Wettable sulphur powder—IS: 3383-1965		
6	CM/L-2406 11-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	Jayalakshmi Agro Chemicals, Amaravathi Road, Gorantla Village Limits P.O., Guntur-2, Guntur Distrit, Andhra Pradesh	BHC dusting powders—IS:561-1962		
7	CM/L-2407 11-9-1970	16-9-19 7 0	15-9-1971	Aluminium Udyog, 15, Daspara Road, Calcutta-4 [Office: 174, Mahatma Gandhi Road, (2nd Floor), Calcutta-7]	Barrel tower bolt (anodised), Type 5-IS: 204-1966		

-		.0ac. 51
,	A-/L	ATIC STATE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20, 1893 471
		CALEI
		TE O
		AIGNI H
		SEP
		LEMBE
		R 11,
		1971/BI
		HADRA
		20, 1
		893
		1717

8	CM/L-2408 11-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	Artee Minerals, 15/7, Mathura Road, Faridabad (Haryana)	Endrin emulsifiable concentrates—İS: 1310-
9	CM/L-2409 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Continental Industries, S 34-39, Industrial Estate, Bapunagar, Ahmedabad-21 (Office: Harisadan, 2nd Floor, Khadia Char Rasta, Ahmedabad-1)	Metal heald frames (i) with wooden lateral supports (ii) with steel lateral supports—IS: 4465-1967
10	CM/L-2410 28-9-1970	1~10-1970	30-9-1971	Ail India Medical Corporation, Simpoli Road, Borivili (West), Bombay-66 (Office: 185, Princess Street, Bombay-2)	Malathion emulsifiable concentrates—IS: 2567-1963
11	CM/L-2411 28-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	A. R. Nag Choudhury & Co., Baruipur, P.O. Baruipur, Distt. 24 Parganas (West Bengal)	Door closers (hydraulically regulated) size 2— IS: 3564-1966
12	CM/J -2412 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	' Sunray Chemical Industries, Moti Lal Nehru Road, Agra.	BHC water dispersible powder concentrates— IS: 562-1962
r3	CM/L-2413 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Ramkrishan Kulwantrai Steels Private Ltd., 403-A, Tiruvottiyur High Road, (Next to Ajax Bus Terminus) Tiruvottiyur, Madras-19 (Office: 35, Sembudoss Street, Madras-1)	Structural Steel (standard quality)—IS: 226- 1969
τ4	CM/L-2414 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Do.	Structural steel (ordinary quality)—IS: 1977-
15	CM L-2415 28-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	Premchand Jute Mills, Lessee: Sonajuli Tea & Industries Ltd. Chengail, Howrah (Office:10, Clive Row, Calcutta-1)	B-Twill jute bags—IS:2566-1955
16	CM/L-2416 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	The Tata Iron & Steel Co. Ltd. Jamshet pur	Cold twisted defomed steell bars for concrete reinforcement—IS:1786-1966
17	CM/2-2417 29-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Dalima Biscuit Private Ltd, Rajpur, District Patiala (Punjab)	Bisuits of the following varieties: Puff cream, glucose milk, nice, butter cream, de-luxe, titbits, cream finger, tea, glucose, chocolate cream, salt, arrow-root, orange cream, coconut, royal, saltee, amar, shorty, pineapple, cream, lemon cream, marie, cocontut coo ies jaffa, oreao and lactose—IS:1011-1968

ř	4-
Ì	716
	4716 THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20, 1893
ì	Ð
[ZΣ
ĺ	T
1	ΈC
1)F
١	Z
ļ	ĄĮ
	SE
1	T
į¦	ΕM
	BE.
1	, F
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
ľ	971
1	B
١	HA
ļ	2
ļ) N
1	۶,
•	893

1	2	3	4	5	6
18	CM/L-2418 30-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	Multiplex Agro Industries Private Ltd., Plot No. 184/11 & 184!12, Naroda Industrial Estate, Naroda, Ahmedabad.	BHC dusting powders—IS: 561-1962
					[No. CMD 13:11.]

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1971

एस० ग्रो० 3349—समय समय पर संजोधित भारीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के ग्रामार भारतीय मानक संस्था की ग्रोर से ग्रधिमूचित किया जाता है कि 18 लाइसेंस जिनके वौरे नीचे ग्रनुसूची में दिए हैं लाइसेंस-धारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लमाने का ग्रधिकार देते हुए स्वीभ्रत किए गए हैं:—

ग्रनुसूची लाइसेंस संख्या 🛘 वैधता की ग्रवधि लाइसेम के म्रधीन वस्तु-/प्रक्रिया लाइसेंमधारी का नाम ग्रौर पता क्रम ग्रौर तत्सम्बन्धी भारतीय सानक संख्या (सी एम/एल−) IS: पद नाम तक (1)(2) (3) (6)(4)(5) सी एम / एल--2401 ग्राध्र स्टील कारपोरेशन लि॰, मतकापुरम् , ठडी मरोड़ी वाली इस्पात की विक्रुत 1-9-1970 1-9-1970 विशाखापटनम बन्द्रगाह, ग्रांध्र प्रदेशी IS. 1786-1966 ¦कार्यालय : थोम्सन स्ट्रीट, विणाखा 🕢 पटनम (म्रांध्र प्रदेश] ॰ मो एम डी/एल-2402 16-9-1970 वेल्लित पीतल की पट्टिया ---**कृष्ण इंत्रो**नियरिंग इन्डस्ट्रीज,न्यू छ७रोली 15-9-1971 CUZN37-3-9-1970 रोड, जगाधरी (हरियाणा) ! IS: 410-1967

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	सो एम/ एल-2403 9-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	मैंसूर मीमेंट लि॰, ग्रदित्यपटना, ग्रम्साद्र डाकघर, जिला तूमक्रूर, मैंसुर राज्य, [कार्यालय :1—विद्यान विधि, काफी बोर्ड बिल्डिंग (पांचवीं मंजिल), बंगलौर में है]	साधारण पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट — IS: 269-1967
4	सी एम / एल—2404 10—9—1970	16-9-1970	15-9-1971	रोगल प्रॉडक्ट्स प्रा० लि०, 186-रोयापेच रंज हाई रोड, रोयापेय -मद्रास-14	कों से बनी फाउंटेनपेन की स्याही - नीली — IS: 1221-1957
5	सी र्म / एल-2405 11-9-1970	1-10-1970	3 0-9-1971	भारत पुल्वराइजिंग मिल्स प्रा० लि०,1074 —–तिख्वोतियुर हाई रोड, मद्रास–19	म्रार्दनयोग्य गंधक चूर्ण IS: 33831965
6	सी एम / एल2406 11-9-1970	16 -9- 1970	15-9-1971	जयलक्ष्मी एग्रो क्रैमिकल्स, ग्रमरावती रोड, गोरनतल्ला गांव ग्रंत डाकघर,गंटूर-2 गंटूर जिला (ग्रांध्र प्रदेश)	बी एच सी घूलन पाउडर IS: 561−1962
7	सी एम / एल⊷2407 11−9−1970	16-9-1970	15-9-1971	एल्युमिनियम उद्योग, 15, दासपारा रोड, कलकत्ता-4 [कार्यालय : 174-महात्मा गांघी रोड, (तीसरी मंजिल), कलकत्ता-7 में है]	टाइप-5
8	सी ए म/ एल -2408 11-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	ग्ररती मिनरल, 15/7, मथुरारोड, फरीदा- एर् बाद (हरयाणा)	ण्डून पायसनीय तेज द्रव IS: 1310-1958

[कार्यालय : हरीसदन-तीसरी मजिल, खादिया चार रोस्ता, महमदाबाद-1 में है] 28-9-1970 10 सो एम / एल-2410 28-9-1970 11 तो एम / एल-2411 28-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 16-9-1970 15-8-1971 1	9 सी एम / एल-240 28-9-1970	09 1-10-1970 30 - 9-199	यल इस्टेट, बापूनगर ब्रहमदाबाद-21 (1) पीछे लकडी के सरक्त
प्राम् द्वारण कुलवन्तराय स्टीत्स प्रा० लि०, संरचना इस्पात (मानक किस्म) (अंगंक्स बस स्टेन्ड के पास) तिस्वी- तियर-मद्रास-19 [कार्यालय : 35- थ-१-१७७० विस्तर-मद्रास-1 में है] -नैसाही- संरचना इस्पात (साधायण ६)	10 सो एस / एल−2410 28−9−1970	I-10-1970 30-9-1971	(2) पीछे इस्पात के ग्राधार वाले IS: 4465-1967 बादिया चार रास्ता, ग्रहमदाबाद-1 ग्राहे हैं] ग्राल इंडिया मेडिकल कारपोरेशन सिमपोली मालाश्रियोन प्राप्ति के श्राधार वाले मालाश्रियोन के श्राधार वाले मालाश्रियोन प्राप्ति के श्राधार वाले मालाश्रियोन प्राप्ति के श्राधार वाले मालाश्रियोग के श्राधार वाले मालाश्रियोच के श्राधार वाले मालाश्रियोन के श्राधार वाले मालाश्रियों के श्राधार वाले मालाश्रियों के श्राधार वाले मालाश्रियोच के श्राधार वाले मालाश्रियों के श्राधार वाले मालाश्रियों के श्राधार वाले मालाश्रियों के श्राधार वाले मालाश्री क
प्राम् द्वारण कुलवन्तराय स्टीत्स प्रा० लि०, संरचना इस्पात (मानक किस्म) (अंगंक्स बस स्टेन्ड के पास) तिस्वी- तियर-मद्रास-19 [कार्यालय : 35- थ-१-१७७० विस्तर-मद्रास-1 में है] -नैसाही- संरचना इस्पात (साधायण ६)	11 सी एम / एल-2411 28-9-1970	16-9-1970 15-9-1971	[कार्यालय : 185, प्रिसेस स्ट्रीट, बम्बई - 2 में है] ए० ग्रा॰ नाग नौधरी एएड हो -
प्राम् द्वारण कुलवन्तराय स्टीत्स प्रा० लि०, संरचना इस्पात (मानक किस्म) (अंगंक्स बस स्टेन्ड के पास) तिस्वी- तियर-मद्रास-19 [कार्यालय : 35- थ-१-१७७० विस्तर-मद्रास-1 में है] -नैसाही- संरचना इस्पात (साधायण ६)	12 सो एम/ र्ल-2412 28-9-1970		पुर-डाकवर, बरूश्रापुर, जिला— 24 परगना, (प० बंगाल) सनरे केमिकल इंडस्ट्रीज, मोलीलाङ वे
4 सी एम / एल -2414 1-10-1970 30-9-1970 नियर-मद्रास-1 में है] 28-9-1970 नियर-मद्रास-1 में है] -नैसाही- संरचना इस्पात (सामावण ६	13 सी एम / एल−2413 28−9−1970	1-10-1970 36-9-1971	रामञ्चल्या कुलवन्तराय स्वीत्रास्त्र । IS: 562-1962
	4 सी एम / एल -2414 28-9-1970	-10-1970 30-9-1970	(अजंक्स बस स्टेन्ड के पास) तिरूवी- तियर-मद्रास-19 [कार्यालय: 35- शम्मूदास स्ट्रीट, मद्रास-1 में है] -नैसाही- संरचना इस्पात (साधारण किस्म)- IS: 1977-1969

)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
. 5	सी एम / एल-2415 28-9-1970	16-9-1970	15-9-1971	प्रेमचन्द जूट मिल्स, लैसी : संजोली टी० एण्ड इंडस्ट्रीज, लि०, छेगायल, हावड़ा । [कार्यालय : 10क्लाइव रोड, कलकत्ता में है]	बी- ट्विल जूट के बोरे — IS: 2566-1955
16	सो एम/एल-2416 28-9-1970	1-10-1970	30-9-1971	दि टॉर्टा ग्रायरन एण्ड स्टील क्रं० लि०, जमश्चेदपुर	क्रंकीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोडी इस्पात की विद्धत छड़ें — IS: 1786—1966
17	सो र्म/र्ल−2417 29−9−1970	1-10-1970	30-9-1971	डालिमया बिस्कुट प्रा० लि०, राजपुरा— जिला पटियाला, (पंजीब)	निम्नलिखित किस्म के बिस्कुट- पफ कीम, गुलूकोस दूध, नाइस, मक्खन कीम, डी-लक्स, टिटबीट्स कीमर्किंग, टी, गुलूकोस, चाकलेट कीम, नमकीन, एरो-रूट, रूप्रौरेंज कीम काकोनट, रायल, नमकीन, ग्रमर शोरटी, पाइन ऐपल कीम, लेमन कीम, मेयरी,को कोनट, कूकीज जाफा, ग्रोरियो ग्रौर लेक टोज —— IS: 1011-1968
18	सो एत∕ एल−2418 30−9−1970	1-10-1970	30-9-1971	मल्टीपलेक्स एग्नो ईन्डस्ट्रीज प्रा० लि०,प्लांट सं० 1841/11ग्रौर 184/12, नरोदा, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नरोदा, ग्रहमदाबाद ।	बी० एच०सी०धूलन पाउडर — IS: 561-1962

New Delhi, the 26th July 1971

S. O. 3350.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as am ended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-1920, particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 July, 1971, since IS:4369-1967 has been superseded by IS:1875-1970 after 30 June, 1971.

Sl. Licence No. & Name and Address Article/Process covered Relevant Irdian No. To Date of the Licensee by the licence cancel—Standard led

J. CM/L-1920, 17-2-1969 The Indian Iron & Steel Co. Ltd.(Burnpur Works) P.O. Burnpur, Distt. Busdwan West Bengal.

Carbon Steel Bars for Forgings Class I & II only. IS: 4369-1967 specification for carbon Steel Bars for Forgings.

[No. CMD/55: 1920]

A. K. GUPTA, Dy. Director General.

नई दिल्ली, 26 ध्रगस्त 1971

एस० प्र.० 3350.—समय समय पर संगोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन बिन्ह) विनियम, 1955, के विनियम 14 के उपितियम (4) के प्रमुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा सुचित किया जाता है कि लाइसेंस सं या सी एम/एल-1920 जिसके व्यौरे नीचे दिए गए हैं दिनांक 1 जुलाई 1971 से रद्द कर दिया गया है, क्यांकि 30 जून 1971 के बाद 1875-1970 के प्रकाशन से 18:4369-1967 रद्द हो गया है:

	लाइसेंस सं०	लाइसेंसघारी का नाम	रद्द किए गए लाइमेंस	तत्सम्बन्धी भारतीय
स०	भ्रौर तारीख	भ्रोर पता	के स्रधीन वस्तु/प्रक्रिया	मानक

मी एम/एल 1920 दि इंडियन श्रायरन एण्ड गढ़ी चीजों के लिए IS: 4369-1967 17-2-1969 स्टील कं लिल, (बर्न- कार्बन इस्पात की छड़ें गढ़ी चीजों के लिए पुर नक्से), डाकघर केवल 1 श्रीर 2 श्रेणी की कार्बन इस्पात की छड़ों वर्नपुर, जिला बर्दवान की विशिष्टि (प० वंगाल)

[सँ० मी: एम डी:/55:1920]

ए० के० गुप्ता, उप-महा निवेशक ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd July 1971

S.O. 3351.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhu D. Patel, C/o Dr. K. N. Jani, M.B.B.S., Tarota Bazar, Navsari, Gujarat a contesting candidate for election to the House of People from 22-Surat Constitutency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure:

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prabhu D. Patel to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-HP/22/71.]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy

भारत निर्वाचन व्याय ग

भारते दर

नई दिल्ली, 22 जुलाई 1971

एस० श्रे े० 3351.— -यतः, निर्वाचन श्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 22—सूरत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदयार श्री प्रभृ डी० पटल, मार्फत डा० के० एन० जानी, एम० बी० बी० एस०, टरोटा बाजार, नवसारी, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व ग्रिधिनयम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से श्रपने निर्वाचन व्यथों का लेखा दाखिल करने में ग्रसफल रहे है.

श्रीर, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये श्रभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चान्, निर्वाचन श्रायोग का यह भी समाधान हा गया है कि उसके पास इस श्रसफलता के लिए कीई पर्याप्त कारण या न्यार्याचित्य नहीं है,

ग्रतः, श्रब, उक्त श्रिधिनियम की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एनद्धारा उक्त श्री प्रभु डी० पटेल को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा श्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने ग्राँर होने के लिए इस ग्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्नाहन घोषित करता है।

[नं **गज-लो** • स॰/22/71]

श्रादेश से,

रोशिन लाल, सचिव №

New Delhi, the 30th July 1971

New Delhi, the 30th July 1971

S.O. 3352.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (VII of 1922), the Central Government hereby appoints Shri H. Kasim Khan, Protector of Emigrants, Mandapam Camp and Tuticorin, to be Protector of Emigrants, Nagapattinam, in addition to his own duties with effect from the forenoon of 1st July, 1971, during the absence on leave of Shri B. V. S. Rao.

[No. CPEO/6/71.]

[No. F. 3(24)V-IV 160.]

K. S. SODHI, Under Secy. (P.V.A.)

विवेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1971

का० ग्रा० 3352.— उत्प्रवास ग्रधिनियम 1922 (1922 का सात) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त ग्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, श्री एच. कासिम खां, उत्प्रवासी संरक्षक, मण्डपम कैम्प ग्रीर तूतीकोरिन को, श्री बी. वी. एस. राव के ग्रवकाश पर अनुपस्थित रहने के दौरान, उनके अपने कार्यों के ग्रतिरिक्त, 1 जुलाई, 1971 के पूर्वाहिन से नागपट्टिनम् में भी उत्प्रवासी संरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० सी पी ई ग्रो /6/71] कुलदीप सिंह सोधी, श्रवर सचित्र।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 7th August 1971

S.O. 3353.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Junction Point to Kalol Industries in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For laying the line for Kalol Industries Gas Distribution line

State: Guiarat

Dist: Mehsana

Taluka Kalol

Village			Survey No.	Hectare	Are.	P. Are.
Saij		 	 220	0		40
•			219	0	5	40 40
Kalol			281	0	3	72 20
			284 285 286	0	4	
			285	0	6	24
			286	0	5	24 64
			287	0	6	oo .

[No. 11(4)/71-Lab.& Legis.]

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय

(पेट्रें।लि रम बिभाग)

नई दिल्ली 7 अगरन, 1971

का० आ० 3353.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवण्यक है कि गुजरात राज्य में कुन्नां संख्या जंक्यन प्याइंट से क्लोल उद्योगों तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जानो चाहिए।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदवाबद्ध श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार श्रीजित करना श्रावश्यक है:

श्रतः, श्रव, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के श्रधिकार का श्रजंन) श्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्षयों का प्रयोग करते हुए केन्त्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार श्राजित करने का अपना श्राशय एतद्वारा घोषित किया है। बशर्तों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए श्राक्षेय सक्ष प्राधिकारी, ——०००——००० तेल तथा प्राकृतिक गैस श्रायोग, निर्माण श्रौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बरौदा—१ को इस श्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

श्रौरऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिणः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फातः।

श्रनस'ची

कलोल इंडस्ट्रीज गैंस डिस्ट्रीब्य्शन लाइन के लिये पाइनलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात ————————	ाजलाः ग	म्हसाना ——	<u></u>	लुकाः ————	कलाल
गांव	सर्वेक्षण	संख्या हैक्टर	ए फ्रार डी	पो० ए ऋ	ार ई
		220	0	5	40
		219	0	5	40
कलोल		281	0	3	72
		284	0	4	20
		285	0	6	24
		286	0	5	64
		287	0	6	00

[संख्या 11(4)/71-लेबर एण्ड लेजिय]

New Delhi, the 12th August 1971

S.O. 3354.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 91 to GGS II in Kalol oil field Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexted hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Line From Well No. 91 To GGS II.

STATE: GUJARAT

DIST: MEHSANA

TALUKA: KALOL

Village	S, No.	Hectare	Arc	P. Are.	
I	2	3	4	5	
Dhanoj	V.P. Cart track	0	0	61	
,	39	Ó	3	01	
2)	38	0	5	12	
دو.	40	0	0	25	
- 9 9	56	0	14	27	
"))	57	0	7	93	
22	59	0	8		
22	61	0	2	78 68	
))	62	0	9	09	

	2	3	4	5
hanoj	69/2	0	4	82
33	63	0	6	16.
,,,	64	0	19	28
33	66	0	4	27
,	67	0	I	28
**	64	0	4	51
,,	V.P. Cart track	0	ó	55

[No. 11(4)/71-Lab. & Legis.] N. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली 12 भगस्त, 1971

कार प्रांत 3354.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतित होता है कि लोकहित में यह श्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में क्लोल तेल क्षेत्र में कुश्रा संख्या 91 से जी जी एस II. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्रावृतिक गैस श्रायोग द्वारा विछ।ई जानी जाहिए।

ग्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध श्रनुसूची। मैं विश्वित भूमि में उपयोग का अधिकार श्रीजत करना श्रावश्यक है:

ग्रतः, श्रव, पैट्रोलियम पाइप्लाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिक्षिकार का ग्रर्जन) श्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का ग्रिधिकार श्रृजित करने का श्रुपना ग्रामय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उदत भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल सथा प्राकृतिक गैस आयोग, दिर्माण ग्रीर देख-भाल, प्रभाग मकरपुरा रोड, बरौदा-9 को इस ग्रधिसूचना की तारीख ले 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

न्नीर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधि टत ः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

श्रमृसूची क्थ्रा संख्या 91 से जी जी एस II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्यगुजरात	जिला—महसाना		तालुका—क्लोल [*]		
गांथ	सर्वेक्षण संख्या	हक्टर	ए ग्रारई	पी० ए श्रार ई	
1	2	3	4	5	
धनौज	वी०पी० कार्टट्रैक	5 O	0	61	
,,	39	0	3	10	
11	38	0	5	12:	
"	40	0	0	25	
11	5 6	0	14	27	
11	37	0	7	93	

Sec. 3(ii)] THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20, 1893 4727

1	2	3	4	5
ध দ্বীज	59	0	8	78
,,	61	0	2	68
11	62	0	9	09
,,	69/2	0	4	82
; ;	63	0	6	16
11	64	0	19	28
33	66	0	4	27
11	67	0	1	28
11	64	0	4	51
11	वी० पी० कार्टट्रेक	0	0	55

[संख्या 11(4)/71-लेवर एण्ड लजिस]

एन० श्रीनिवासन, भ्रवर सचित्र ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th June 1971

- S.O. 3355.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule 2 of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby reappoints following persons as members of the Advisory Panel of Central Board of Film Censors at Bombay with effect from 1st July, 1971 to 30th September, 1971:
 - 1. Smt. Maniben Desai
 - 2. Smt. T. V. Debejia
 - 3. Shri Nassim Ezekiel
 - 4. Smt, Laxmi Wahi
 - 5. Shri S. D. Shah
 - 6. Shri Ganga Ram Joshi
 - 7 Shri Rama Narang
 - 8. Shri U. A. Thadani
 - 9. Shri R. K. Soni
 - 10. Shri S. E. Hassnain
 - 11. Smt. Kamala Dua
 - 12. Shri Talakshi Shah

[No. F. 11/3/71-F(C).]

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्राजय

नई दिल्ली, 29 जून, 1971

एस॰ भो॰ 3355.—चलचित्र श्रधिनियम, 1952 की धारा 5 (1) ग्रौर चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम 2 के साथ पठित नियम, 8 के उप-नियम (3) श्रारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, एत्द्रहारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को

1 जुलाई, 1971 से 30 सितम्बर, 1971 तक केन्द्रीय फित्म सेसर बोर्ड के बग्दर्श सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य निय्वत किया है।

- 1 श्रीमती मनीबेन देसाई
- 2 श्रीमती टी ० वी देहे जिया
- 3 श्री नर्साम एजेकील
- 4 श्रीमती लक्ष्मी वाही
- 5 श्री एस० डी० शाह
- 6 श्री गंगा राम जोशी
- 7 श्री राम नारंग
- 8 श्रीयु० ए० थडानी
- 9 श्री भ्रार० के० सोनी
- 10 श्री एस ० ई ० हसनैन
- 11 श्रीमती कमला दुश्रा
- 12 श्रीतलाशी शाह

[संख्या फा॰ 11/3/71-एफ (सी)]

- S.O. 3356.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby re-appoints the following persons as members of the Central Board of Film Censors with effect from 1st July, 1971 to 30th September, 1971.
 - 1. Shri B. R. Agarwal
 - 2 Shri V. R. Mohan.

[No. F. 11/5/71-F(C).]

VIRENDRA D. VYAS, Director.

एस • भो • 3356.— - चल चित्र प्रधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त श्रिधिनारो वा प्रयोग का ते हुए, बेन्द्रीय सरकार ने एत्द्द्वारा निम्निलिखित व्यवितयों को 1 जुलाई, 1971 से 30 सितम्बर, 1971 तक बेन्द्रीय, फित्म मेसर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुवत किया है—-

- 1 श्रीबी० भार० अग्रवाल
- 2 श्री वी० श्रार० मोहन

[संख्या फा० 1 ! / 5 / 71 - एफ ० सी ०]

वीरेन्द्र देव व्यास, निदेशक ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Experts)
(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 3rd May 1971

S.O. 3357.—M/s. Ajudhia Nath Surender Nath, 468/VI-3, Majith Mandi, Amritsar were granted as established import licence No. P/EI/0173062/C/80/33-D/30-31/Adhoc/No. dated 31/10/69 valid upto 30/6/70 for Rs. 5000/- for import of Dates

from Iraq. They have applied for the duplicate copy of the Custom purpose copy of the said licence on the ground that the original custom purpose copy of the said licence has been lost. It is further stated by the firm, that original custom purpose copy of the licence was registered with the Collectorate of custom, Bombay and was utilised for Rs. 3,000.

In support of this declaration, the applicant has filed an affidavit duly attested by Oath Commissioner, Delhi stating that the original C.C.P. of the licence has been lost.

I am satisfied that the original licence No. P/E1/0173062/C/BQ/33/D30-31/Ad hoc NQQ/CLA dated 31/10/69 valid upto 30/6/70 has been lost and direct that a duplicate licence should be issued to the applicant. The original licence is cancelled.

[No. F. 21(B)-IV/627/Iraq/SA.70/Indo-swa/CLA.] R. L. VARMA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश ब्यापार मंत्रालय

संपुरत मुख्य नियत्रक, द्यायात-निर्यात का कार्यासय

केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र

श्राक्षेत्र

नई दिल्लीः, 3 मई, 1971

एस ० % २० 3357.—सर्वश्री श्रयोध्या नाथ सुरेन्द्र ाथ, 468/6-3, मजीठ मंडी, श्रमतसर को ईराक से खजूरों के ब्रायान के लिए 5,000/- रुपये का एक संस्थापित ग्रायात लाइसेंस संख्यापी/ई/ब्राई/0173/62/मी/पी क्यू/33/डी/30-31/एइहाक /एन क्यू क्यू दिनांक 31-10-69 जो 30-6-70 तक वैध था, स्वीवृत किया गया था। उन्होंने उनत लाइसेंस की श्रनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए इस श्राधार पर कार्यदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है। फर्म द्वारा श्रामें यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो मा-शुल्क समाहर्ता, बम्बई के पास पजीवृत की गई थी श्रीर 3000/-रुपये तक के लिए उसका उपयोग किया गया था।

इस घोषणा के समर्थन में श्रावेदक ने शपथ-ग्रायुक्त द्वारा विधिवत साक्षांकित एक शपथ-पत्न यह बताते हुए जमा किया है, कि लोईसेस की मूल सीमा-णुक्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है।

मैं इससे संतृष्ट हूं वि मूल लाइसेंस संध्या पी/ई/स्राई/0173062/सी/पीनयू/33/डी/30-31 एउहाक एन क्यू क्यू/सीएलए, दिनांक 31-10-69 जो 30-6-70 तक वैध था खो गया है स्रौर निदेश देश है कि स्रावेदक को स्नुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए।

[अंख्या : 21 (बी)-4/627/ईराक/एसए-70/इन्डो-स्व/सीएलए]

भ्रार० एल० वर्मा,

उप-मुख्य नियंत्रक, श्रायात-नियति ।

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports) ORDER

New Delhi, the 17th May 1971

SUBJECT.—Cancellation of Licence No. P/L/2599100 dated 5-11-69 (Exchange Control Purposes Copy) issued to M/s. The Empire Dyeing and Mfg. Co. Ltd., Bombay.

Bombay.

S.O. 3358.—M/s. The Empire Dyeing & Mfg. Co. Ltd. Bombay have been granted Licence No. 2599100 dated 5-11-69 for Rs. 6,669/- (Rupees Six Thousand Six

Hundred and Sixty Nine only) for import of 1. Natural Dense Soda Ash 2. Arsenic 3. Cobalt Oxide 4. Nickel Oxide 5. Selenium 6. Antimony Oxide 7. Ceramic Colours 8. Potassium Carbonate 9. Titanium Dioxide (Rutile Grade) 10. Iso Amyl Acetate 11, Isobutanol 12, Rough Blanks upto 25 per cent 13, Wire/Welded Wire Mesh 14. E-Glass Marbles 15. Electrocast Refractories 16. Sodium Silico Fluoride upto 10 per cent under the Registered Exporter's Scheme.

They have applied for issue of duplicate copy of Exchange Control Purposes Copy of the said licence on the ground that the Original Licence has been lost.

It is further stated that the said original licence is not registered with the Customs and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Exchange Control Purposes of Licence No. 2599100 dated 5-11-69 has been lost and direct that the duplicate copy of the licence should be issued to the applicant firm.

The original Exchange Control Purposes copy is cancelled.

[No. 265A/83464/AJ 69/L/EPSC IVA/315.] D. D'SOUZA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, म्रायात-निर्यात का कार्यालय)

द्यादेश

बम्बर्ड 17 मई. 1971

विषय — सर्वश्री एम्पायर डाइंग एंड मैनु हैक्चिर्रिंग कं० नित्, बम्बई के नाम जारो किए गए लाइसेंस संख्या : पी/एल/2599100, दिनाक 5-11-69 (पुरा विनिमय नियंत्रण प्रति) को रह करने का खादेश ।

एस॰ भ्रो॰ 3358 — सर्वं श्री एस्पायर डाइंग एंड मैंनुकैक्वरिन्ग क॰ लि॰, वस्वई को गजो कृत निर्यातक योजना के भ्रन्तर्गत 1 प्राकृतिक डैन्स सौडा एश, 2 भ्रसोनिक, 3 को बाल्ट भ्रावसाइड 4 निकल भ्रावसाइड, 5 सेलिनियम 6 एनेटिमोनि भ्रावसाइड, 7 सिरामिक ंग, 8 ोटेशियम कार्बोनेट, 9. टिटानियम डायक्साइड (रूटाइल ग्रेड) 10 भ्राहसो भ्रमाइल एसिटेट, 11 श्राइसोब्टानौल, 12. 25 प्रतिशत तक रफ ब्लैक्स, 13 तार/बैल्ड की हुई वायर मैंग, 14 ई-लास मार्बेन्स, 15, इलैक्ट्रोकास्ट रिफैक्ट्रीज, 16 10 प्रतिशत तक सोदियम सिलिकों क्लोराइड के भ्रायात के लिए 6,669 रुपये का लाइसेंस संख्या 2599100 दिनांक 5-11-69 प्रदान किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंप की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस प्राधार पर श्रावेटन किया है कि मल लाइसेंस खो गया है।

भ्रागे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस सीमा-भृत्क कार्यालय के पास पंजीकृत नीं किया गया है भ्रीर उसका उपयोग नहीं किया गया है।

ग्रपने तर्क के समर्थन में भ्रावेदक ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस मंख्या 2599100 दिनांक 5-11-69 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है श्रौर निदेश देता हं कि श्रावेदक को श्रनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए ।

मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रह की जाती है।

[मिसिल संख्या 265 ए/93464/ए जे 63/एल/ईपीएससी-4 ए/315]

डी. डि-सूजा,

उप-मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 4th August 1971

S.O. 3359.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Neyyoor Mekkankara Milk Supply Co-operative Society Y. 36, West Neyyoor Post, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S. 35019(49)/71-PF.II.]

थम श्रीर पुनर्यास मंत्रालय

(अभ और रेजागर विभाग)

नई दिल्ली, 4 ग्रगस्त, 1971

का० भ्रा० 3359.—पत: केन्द्रीय परकार को यह म तोत होता है कि दि रेमकर मेक्कानकारा िल्क सप्लाई को-भ्रापरेटिव सोसाइटी वाई० 36, बैस्ट नेयकर पोस्ट, कन्याकुमारी जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियो की . बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब देंगन निधि ग्रिशिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

म्रतः, स्रबं, उक्तं प्रधिनियमं की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदश्तः सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्तः अधिनियम के उपबन्ध उक्तं स्थापन को एनद्वारा लागू करती है।

यह ऋजि रूचना 1971 की अभैज के अभन दिन हो हुई अनुसा सनझी जाऐगी।

[सं० एस-350/3(49)/71-पी०एफ०]

New Delhi, the 18th August 1971

S.O. 3360.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2261 dated the 31st May, 1969 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Orissa in which the provisions of Chapter IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

Sl. No. Name of District			Name of Area	Name of the Factory		
(1)		(2)	(3)	(4)		
1.	Ganjam		Gosaninu aga on Khallikote	M/s Bijoya Saw Mills. The Kallikote Co-op. Works.	Wood	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Keonjhar	Baliparbat	The Orissa State Commercial Transport Corporation Work- shop.
3.	Koraput	Chitrakunda	Saw Mill under Orissa Forest Corporation Ltd.
4.	Mayurabhang	Baripada	The Regional Co-op, Marketing Society Ltd.
5-	Puri	Satsankba	 The Orissa Fibre. The Indian Latex Fibre Corporation.
6,	Sambalpur	Banaigarh	Baniagarh Industrial Co-op. Society. Ltd.

[F. No. S-38017(15)/71-HI.];

नई दिल्ली, 18 ग्रगस्त, 1971

कार प्रात् 3360.—कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम भौर रोजगार विभाग) की प्रधिसूचना संव काव आव 2261 तारीख 31 मई, 1960 के श्रमुटर्तन में के ब्वीय सरकार को इससे उपावड श्रमुस्वी के स्तम्भ (4) में विनिद्धिट कारखानों की श्रविधित को ध्यान में रखते हुए उक्त श्रमुस्वी के स्तम्भ (3) में विनिद्धिट उड़ीसा राज्य के ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 4 श्रीर 5 के उपवन्ध प्रवृत्त नहीं है, उक्त कारखानों को उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 5-क के श्रधीन उद्महणीय नियोजक के थियोष श्रभिदाय के सन्दाय से, उक्त श्रिस्मा में श्रविनिद्धिट श्रविधि की समाप्ति की तारीख में एक वर्ष की श्रविध के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त श्रिधिनियम के श्रध्याय 5 के उपवन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

भ्रनुसूची

ऋम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गंजाम	गोसानिनुवागांव खलिकाट खलिको	मेसर्स विजोय सा मिल्स। दि खलिकोट को-ग्राप० वुड वर्क्स।
2.	केर्प्राक्षर	बालि पर्वतः	दि उडीसा स्टेट कर्माशयल ट्रान्स ⁻ पोर्ट कारपोरेशन वर्कणाप ।
3.	कोरापुट	चित्रकण्ड	उड़ीसा कारैस्ट कारपोरेशन लिमिन टेड के श्रधीन सा मिल ।

(1)	(2)	(3)	(1)
4.	मयुरभंज	बारीपादा	दि रिजनल को०-भ्राँप०-मारके- टिंग सोसाइटी लिमिटेड।
5.	पुरी	सत्संकबा	 दि उड़ीसा फाइबर। दि इन्डियन लेटैंक्स फाइबर कारपोरेशन।
6.	सम्भलपुर	बनाइगढ़	बनाईगढ़ इन्डस्ट्रियल को०-म्रॉप० सोसाइटी लिमिटेड ।

[स॰ फा॰ एस-38017 (15)/71-एच॰ प्राई०]

S.O. 3361.—Whereas the Central Government was satisfied that Champakalal and Co., Jarda Factory, was situated in Mogar area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Kaira in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 137, dated the 9th January, 1962,

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Mogar area in the district of Kaira in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

New, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely.—

In the Schedule to the said notification against Scrial No. 10 the entry "Mogar" in column 3 and the entry corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[F. No. 603(1)/70-I4I.]

कां थार 3.61.—य: वेन्द्रीय सरवार वा यह समाध न हो गया था कि चम्पवलाल एण्ड कंपनी जरदा पैन्टरी मोगार क्षेट्र में श्रवस्थित थी, जो गुजरात राज्य के कैरा जिले में बिखरी हुई श्राबादी का क्षेट्र (श्रथीत ऐसा क्षेत्र जिस्की बीमा योग्य श्राबादी 500 से कम थी) था;

श्रीर यतः, उनके विरासी हुई आवार्य के क्षेत्र में श्रयस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारख ने को, भारत सरकार के भृतपूर्व श्रम श्रीर रोजगार मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या का ब्या 137, तारीख 9 जनवरी, 1862 द्वारा वर्मचारी न ज्य बीमा श्रिधिनियम, 1948 (1942 का 34) की धारा 73 द के श्रधीन नियोजक के विशेष श्रीभदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस श्रीधिनियम के श्रध्याय 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रयतित नहीं हो जाते;

आंर यतः केन्द्रीय २२४१४ का यह समाधान हो गा है वि गुजरात राज्य के कैरा जिले में गंगा? क्षेत्र की बीमा योग्य श्राबादी श्रव 500 से बढ़ गई है, आंर अह श्रव विखरी हुई श्रावादी का क्षेत्र गहीं है; भ्रतः, श्रव, कर्मचारी राज्य बीमा श्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिसूचना में एतद्द्वारा श्रीर श्रामे निम्नलिखित संगोधन करती है, श्रर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में कम सं या 10 के सामने स्तंभ 3 में "मोगार" प्रविष्टि ग्रीर स्तंभ 4 में उसकी तत्त्थानी प्रविष्टि लु'त कर दी जाएगी।

[संख्या का॰ 603(1)/70-एच॰ प्राई॰]

S.O. 3362.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 262 dated the 7th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the 220 K. V. Sub-Station Sahupuri, belonging to the Uttar Pradesh Electricity Board, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act in force hereby exempts the said Sub-station from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a Jurther period of one year with effect from the 1st August, 1971 upto and inclusive of the 31st July, 1972.

[No. F. 602(28)/70-HI.]

कार गाउ 3362—कर्मचारी राज्य बीमा प्रिधित्यम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रौर रोजगार विभाग) की श्रिधिसूचना संख्या का श्रा० 262, तारीख 7 जनवरी, 1971 के श्रनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश इलक्ट्रीसिटी बोर्ड 220 कि व्या० सब-स्टेशन साहु-पुरी की श्रवस्थित को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 4 श्रौर 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, उक्त सब-स्टेशन को उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 5-क के श्रधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के जिशेष श्रभिदाय के सन्दाय से 1 श्रगस्त, 1971 से 31 जुलाई, 1972 तक जिसमें जुलाई, 1972 का 31वां दिन भी सम्मिलत है, एक श्रौर वर्ष की श्रवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[फा॰ संख्या 602(28)/70 एच॰ धाई॰]

S.O. 3363.—Whereas the Central Government was satisfied that Shree Mahalaxmi Lime Works was situated in Mogar area which was a sparse area (that is an area whose insurable population was less than 500) in the district of Kaira in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1349, dated the 10th April, 1964;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Mogar area in the district of Kaira in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 5, the entry "Mogar" in column 3 and the entry corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(1)/70-HI.]

का ॰ का ॰ विश्व विकास स्थाप का पह समाधान हो गया था कि श्री महालक्ष्मी लाइम वर्क्स मोगार क्षेत्र में श्रवस्थित था जो गुजरात राज्य के कैरा जिले में बिखरी हुई श्राबादी का क्षेत्र (श्रयात एसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य श्राबादी 500 से कम थी) था;

श्रीर, यत: उसकी विखरी हुई स्रावादी के क्षेत्र में श्रवस्थित के श्राधार पर वेन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम श्रीर रोजगार मत्रालय की श्रधिस्चन। सरया का ब्या • 1349, तारीख 10 श्रश्रील, 1964द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा श्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च के अधीन नियोजक के विशेष श्रीभदाय के सन्दाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस श्रिधिनियम के श्रध्याय 5 के उपक्षन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

श्रौरयत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के कैरा जिले में मोगार क्षेत्र की बीमा योग्य श्राबादी श्रब 500 से बढ़ गई है, श्रौर वह श्रब बिखरी हुई श्राबादी का क्षेत्र नही है;

श्रतः, श्रवः, कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सन्कार उक्त श्रधिसूचना में एतद्द्वारा श्रीर श्रागे निम्निलिखित संशोधन करती है, श्रर्थात् :---

> उक्त श्रिधसूचना की श्रनुसूची में क्रम पंख्या 5 के सामने स्तम्भ 3 में "मोगार" प्रविष्टि श्रीर स्तम्भ 4 मे उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी।

> > [संख्या फाइल 603/1/70-एच० आई०]

S.O. 3364.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 67, dated the 16th December, 1970 the Central Government having regard to the location of the Police Automobile Workshops at Bikaner and Jodhpur in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshops from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1971 upto and inclusive of the 30th June, 1972.

[No. 601(21)/70-HI.]

का॰ प्राः 3364.—कर्मचारी राज्य बीमा प्रधितियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदक्त गिवतयों का प्रयोग करते हुए भ्रौर भारत सरकार के श्रम, रोजगार श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम भ्रौर रोजगार विभाग) की श्रिधिसूचना संख्या का ॰ श्राः 67, तारीख 16 विसम्बर, 1970 के श्रनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार बीकानेर भ्रौर जोधपुर के पुलिस श्राटोमोबाइल वर्कशाप की श्रवस्थित को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त श्रधिनयम के श्रध्याय 4 भौर 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, उक्त वर्कशापों को उवत अधिनयम के श्रध्याय 5-क के श्रधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष श्रभिदाय के संदाय से 1 जुलाई, 1971 से 30 जून, 1972 तक जिसमें जून, 1972 का 30 वां दिन भी सम्मिलित है, एक श्रौर वर्ष की श्रविध के लिए एतद्द्रारा छूट देती है।

[संख्या फाइल 601(21)/70-एच० श्राई०]

8.0. 3365.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the rotification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 260, dated the 7th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, the Haskine Institute Farm, Pimpri (near Poona) in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act, are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 2nd July, 1971 upto and inclusive of the 1st July, 1972.

का० ग्रा॰ 3365.—कर्न चारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रशेग करते हुए ग्रौर भारत सरकार के श्रम, रोजगार ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रौर रोजगार विभाग) की ग्रिधिसूचना संख्या का ०प्रा० 260, तारीख 7 जनवरी, 1971 के प्रमुवर्त्तन में केन्द्रीय सरकार हाफिकन इन्स्टीट्यूट फार्मिपम्परी (पूना के निकट) नामक कारखाने की श्रवस्थित को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में जिसमें उक्त ग्रिधिनियम के श्रध्याय 4 ग्रौर 5 के उपवन्ध प्रवृत्त हैं, उक्त कारखाने को उक्त श्रिधिनियम के श्रध्याय 5-क के ग्रिधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष श्रभिदाय के सन्दाय से 2 जुलाई, 1971 से 1 जुलाई, 1972 तक जिसमें जुलाई 1972 का प्रथम दिन भी सम्मिलित है, एक ग्रौर वर्ष की श्रविध के लिए एतदुद्वारा छूट चेती है।

[सं॰ फा॰ 601(26)/70-एच॰ ग्राई॰]

- S.O. 3366.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2230, dated the 26th May, 1971 the Central Government hereby exempts the monthly rated employees of the Fertilizer Corporation of India Limited, Trombay Division, Bombay from the operation of the said Act except Chapter VA thereof for a further period of one year with effect from the 26th July, 1971 upto and inclusive of the 25th July, 1972.
 - 2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:~
 - (i) The aforesaid factory shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees; and
 - (ii) that, notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have qualified on the basis of contributions paid before the dates of exemption.

[No. S. 38017(19)/71-HI.]

का॰ ग्रा॰ 336 .-- कर्नचारी राज्य बीमा श्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए श्रीर भारत सरकार के श्रम, रोजगार श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रीर रोजगार विभाग) की श्रधिसूचना न ख्या का ॰ 2230 तारीख 26 मई, 1971 के श्रनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, ट्रोम्बे डिवीजन, मुम्बई के मासिक दर वाले कर्मचारियों को उक्त श्रधिनियम के (श्रध्याय 5-क के सिवाय) प्रवर्तन से 26 जुलाई, 1971 से 25 जुलाई, 1972 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक श्रीर वर्ष की प्रविध के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

- 2. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के ग्रधीन रहते हुए होगी, ग्रर्थात् :--
 - (i) पूर्वोक्त कारखाना छूट प्राप्त कर्मचारियों के नामों तथा पदनामों को दिशात करने वाला एक रिजस्टर रखेगा ; श्रार
 - (ii) इस छूट के होते हुए भी कर्न चारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐने फायदे प्राप्त करते रहेंगे जिनके लिए वह छूट की तारीखों से पूर्व सन्दत्त अभिदायों के आधार पर अहित हो गए हों।

[सं० फाइल 38017(19)/71-एच ॰ प्राई०]

S.O. 3367.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3366, dated the 28th September, 1970 the Central Government, having regard to the location of the factory namely, Government Press, Pondicherry, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the

said press from the payment of the employer's special contribution reviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 21st July, 1971 upto and inclusive of the 20th July, 1972.

[No. 601(13)/70-HI.]

का व आ व 3367.—कां चारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का व 3366 तारीख 28 सितम्बर, 1970 के अनुवर्त्तन में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट प्रैस, पांडिचेरी की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवत्त हैं, उक्त प्रेस को उक्त अधिनियम के श्रध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 21 जुलाई, 1971 से 20 जुलाई, 1972 तक जिसमें जुलाई, 1972 का 20वां दिन भी सिम्मिलत है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतदद्वारा छट देती है:

[सं०फा० 601(13)/70-एच० श्राई०]

S.O. 3368.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of Indla in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 259 dated the 7th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Government Press, Rajkot and the Government Photo Litho, Press, Ahmedabad, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1971 upto and inclusive of the 30th June, 1972.

[F. No. 601(20)/70-HI.]

का॰ शा॰ 3368.—कर्मचारी राज्य बीमा श्रिधितयम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त गिवतयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रीर रोजगार विभाग) की श्रिधिसूचना संख्या का॰ श्रा॰ 259, तारीख, 7 जनवरी, 1971 के श्रनुवर्त्तन में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट प्रेस, राजकोट श्रीर गवर्नमेंट फोटो लियो प्रेस, ग्रहमदाबाद नामक कारखानों की अवस्थित को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त श्रिधितयम के श्रध्याय 4 श्रीर 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, उक्त कारखाने को उक्त ग्रिधितयम के श्रध्याय 5-क के श्रधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विणेष श्रभिदाय के सन्दाय से 1 जुलाई, 1971 से 30 जून, 1972 तक जिसमें जून, 1972 का 30वां दिन भी सम्मिलत है, एक श्रीर वर्ष की श्रविध के लिए एतद्दारा छूट देती है।

[सं॰ फा॰ 601(20)/70-एच॰ म्राई॰]

New Delhi, the 21st August 1971

S.O. 3369.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. K. Foundry Service Private Limited 53-Chowringhee Road, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1968.

नई दिल्ली, 21 म्राःस्त, 1971

का० जा० 3369.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एस० के० फाउण्डरीं सर्विस प्रोइवट लिमिटेंड, 53—कौरंगी रोड, कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर परिवार पेंशनः निधि भ्रधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

श्रतः, श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें: हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतव्द्वारा लागू करती है.

यह प्रधिसूचना 1968 के मार्च के इक्त्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

- [सं० एस-35018(30)/71-पी० एक 2]

S.O. 3370.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Globe Rope Works Private Limited, Village Alampore Andul Mouri, Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the 31st day of July, 1970.

[No. S-35018/25/71-PF, II.]

का० ग्रा० 3370.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ग्लोब रोप वक्सें (प्राइबेट) लिमिटेड, गांव ग्रालमपुर, श्रन्दुल मौरी, हावड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर परिवार पेंशन निधि ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उवत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

ग्रतः, ग्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्षत स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह म्रधिसूचना 1970 की जुलाई के इक्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-350/8(25)/71-पी० एफ 2]

S.O. 3371.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Patco Agencies, 18/5, Cambridge Road Cross, Ulsoor, Bangalore-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1971.

[No. S-35019/74/71-P.F.II.]

का० ग्रा० 3371.—-यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेटको एजन्सीज, 18/5, कैम्ब्रिज रोड, फ्रास, उत्सूर, बंगलौर-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध ियोजिक ग्रीर कर्मच रियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रौर परिवार पेंशन निधिः ग्रीधिनयम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

ग्रतः, ग्रब, उक्त श्रिविनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते .हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एनदुद्वारा लागू करती है।

कट प्रधिमुद्धता 1971 के मार्च, के प्राथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी आएगी।

[संख्या एस-350/19 (74)/71-पी एफ 2]

S.O. 3372.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ramesh Saap Mill, 6, Ramesh Nagar (Azadpur), Delhi-33, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1969.

[No. 8(230)/70-PF.II.1

का॰ था॰ 3373.—पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म रमेश सोप मिल, 6 रमेश नगर (आजादपुर), दिल्ली—33 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिनश्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन के लागू किए जाने चाहिए;

भ्रतः, भ्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एउद्द्वारा लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1969 के ग्रप्रैल के प्रथम दिन को प्रगृत हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8(230)/70-पी एफ 2]

S.O. 3373.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Herdilia Chemicals Limited, 9-6 Mile Stone, Thana—Belapur Road, Thana (Maharashtra), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1970.

[No. 8(221)/70-PF. II.]

का॰ आ॰ 3373.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरडीलिया कैमिकल्स लिमिटेड, 9-6 माइल स्टोन, धाना—बेलापुर रोड, धाना (महाराष्ट्र) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रौर कर्जचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर परिवार पेशन निधि ग्रिधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

न्नतः, स्रव, उक्त न्नधिनियम को धारा 1 की उपधारा (4) द्वार प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एनवृद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की जन्बरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8(221)/70~पी० एफ० 2]

S.O. 3374.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Painkulam Co-operative Agricultural Bank Limited, Y. 29, Mukkadu, Painkulam Post, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1971.

[No. S. 35019/50/71-PF.II(i).]

का० आ० 3374.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दि पईनकुलम को-प्रापरेटिव एप्रिकल्चरल बैंक लिमिटेड, वाई०-29, मुक्कडु, एईनकुलम पोस्ट, कन्याकुमारी जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक श्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिष्ठिय निधी श्रीर कृट्मब पेंग्रन निधि श्रीधिनियम 1952 (1952 का 19) के श्रपबन्ध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए;

श्रतः, श्रवं, उवतं ग्रिधिनियमं की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्तं मक्तियों का प्रयोग करते द्विए केन्द्रीय सरकार उक्तं श्रिधिनियमं के उपबन्ध उक्तं स्थापन की एतद्वारा लागु करती है।

यह म्रधिसूचना 1971 की मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

S.O. 3375.—In pursuance of clause (c) of sub-pragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints Sarvashri S. B. Misra and Purshotam Sunderdas as members of the Regional Committee for the State of Orissa and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 1295 dated the 9th April, 1965, namely:—

In the said notification against serial numbers 4 and 6, for the existing entries in the first column, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"Shri S. B. Misra, Chief Personnel Officer, Indian Aluminium Company Limited, Hirakund, Sambalpur District, Orissa"

"Shri Purshotam Sunderdas, Honorary Secretary, Orissa Millowners' Association, College Square, Cuttak-3."

[No. 12/5/65-PF II.]

का० ग्रा० 3375.— कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के खण्ड (ग) के ग्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वेश्री एस० बी० मिश्र ग्रीर पुरुषोत्तम सुन्दरदास को उड़ीसा राज्य के लिए प्रादेशिक समिति के सदस्य नियुक्त करती है ग्रीर भारत सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ग्रधिसूचना संख्या का० ग्रा० 1295 तारीख 9 ग्राप्रैल, 1965 में ग्रीर ग्रागे निम्नलिखित संशोधन करती है, ग्रर्थात् :---

उक्त श्रिधसूचना में क्रम संख्या 4 श्रीर 6 के सामने प्रथम स्तम्भ में विद्मान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों क्रमणः प्रतिस्थापित की जाएंगी, श्रथति :—

"श्री एस० बी० मिश्र ,
मुख्य कार्मिक श्रधिकारी,
इंडियत एल्य्मिनियम कम्पनी लिमिटेड,
हीराकुड, सम्बलपुर जिला,
उडीसा"

"श्री पुरुषोत्तम सुन्दरदास, भ्रवैतनिक सचिव, उड़ीसा मिल श्रोनर्स एसोसिएशन, कालेज स्क्वेयर, कटक—3."

[स॰ 12(5)/65-पी॰एफं॰ 2]

CORRIGENDA

New Delhi, the 18th August 1971

5.0. 3376.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 157 dated the 16th December, 1970 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 9th January, 1971, at page 234, in line 5, for "are in force" read "are not in force".

[No. F. 602(27)/70-HI.]

शुद्धिपक्ष

नई दिल्ली, 18 श्रगस्त, 1971

का ब्रा॰ 3376.—भारत सरकार के श्रम, रोजंगार श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रीर रोजगार विभाग) की भारत के राजपत्न तारीख 9 जनवरी, 1971 भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित श्रधिसूचना संख्या का ब्रा॰ 157 तारीख 16 दिसम्बर, 1970 में पृष्ठ 235 पर प्रथम पंक्ति में "प्रवत्त है" के स्थान पर "प्रवत्त नहीं है" पिछए:

[संख्या फा० 602(27)/70-एच न्य्राई ०]

S.O. 3377.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1141 dated the 22nd February, 1971 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated 20th March, 1971, at page 1358, in line 5, for "are in force" read "are not in force".

[No F. 602(27)/70-HI,]

DALJIT SINGH, Under Secy.

का जिंग 3377.—भारत सरकार के अम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम भौर रोजगार विभाग) की भारत के राजपन्न तारीख 20 मार्च, 1971 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसुचना सख्या का ब्या क 1141, तारीख 22 फरवरी, 1971, में पृष्ठ 1358 पर पांचवी पंक्ति में 'प्रवक्त है'' के स्थान पर 'प्रवक्त नहीं है'' पढ़िए:

[संख्या फा॰ 602(27)/70-एच॰ भाई०]

देलंजीत सिंह, भवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 23rd August 1971

S.O. 3378.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) read with rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby appoints Shri D. C. Berma as a member of the Advisor Committee for the State

of Bihar to represent the interests of the Iron Ore Mine Workers of Bihar State and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 2407 dated the 11th June, 1969 published in the Gazette of India, dated the 21st June, 1969, namely:—

In the said notification, against item 6, for the entry "Shri Gopeswar, Vice-President, Gua Mine Workers Union, Bari Manzil, P.O. Burnpur (Distt. Burdwan)" the entry "Shri D. C. Varma, Vice President, Gua Mines Workers' Union, Post Office Chiria Mines, District Singhbhum, Bihar" shall be substituted.

[No. U-19012/4/71-M. III.]C. R. NAIR, Under Secy-

(धम श्रीर रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1971

का० था० 3378.—लोह श्रयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पठित लोह श्रयस्क खान श्रम कल्याण उपकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त समितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्द्द्वारा बिहार राज्य के लोह श्रयस्क खान कर्मकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री बी० सी० वर्मा को बिहार राज्य के लिए सलाहकार समिति का सदह्य नियुक्त करती है श्रीर भारत के राजपन्न, तारीख 21 जून, 1969 में प्रकाशित भारी सरकार के श्रम श्रीर रोजगार मंत्रालय की श्रिधसूचना का० श्रा० 2407 तारीख 11 जून, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, श्रर्थात:—

उक्त प्रधिसूचना में, मद 6 के सामने ''श्री गोपेश्वर, उप-सभापित गौग्रा खान कर्मकार संघ बाड़ी मंजिल,पोस्ट बुरानपुर (जिला बर्दबान)'' प्रविष्ट के कुथान पर ''श्री डी० सी० वर्मा उपसभापित गौग्रा खान कर्मकार संघ, बाड़ी मंजिल,पोस्ट चिड़िया, माइन्स, जिला सिघभूम, बिहार'' प्रविष्ट प्रति-स्थापित की जाएगी।

[सं॰ यू-190/2/4/71-एम-III]

सी० ग्रार० नैयर, प्रवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 30th August 1971

S.O. 3379.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1162, dated the 25th February, 1971, the Central Government had declared the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for a period of six months from the 4th March, 1971;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to subclause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 4th September, 1971.

[No. F. S. 11025/29/71-LR. I.]

(अम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1971

का० आ०3379.—यतः भारत सरकार के श्रम, रोजगार श्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रीर रोजगार विभाग) की ग्रिशिस्चना संख्या का० श्रा० 1162 तारीख 25 फरवरी, 1971 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लोहा श्रयस्क खनन उद्योग को ग्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनयम, 1947 (1947 का 14) के प्रयोजनों े लिए 4 मार्च, 1971 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित विया

श्रोर यत^{्केन्द्र}ीय सरकार की राय है कि उक्त काल विध का श्रोर ग्रागे छः मास की कालाविध के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में ग्रापेक्षित है ।

मतः, मब मौद्योगिक विवाद मिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (६) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त मिधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 सितम्बर, 1971 से भीर भागे छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11025/29/71-एल०म्रार०1]

एस० एस० सहस्रानमन, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 30th August 1971

S.O. 3380.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Sutna Stone and Lime Company Limited, Satna and their workmen which was received by the Central Government on the 24th August, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Dated July 31, 1971

PRESENT:

Shri M. Chandra, Presiding Officer.

CASE REF. No. CGIT/LC(R) (14) of 1971

PARTIES:

Employers in relation to the Management of M/s. Sutna Stone & Lime Co. Ltd., Satna (M.P.).

Versus

Their Workmen represented by M. P. Stone and Lime Mazdoor Sangh, Satna Siding, Satna (M.P.)

APPEARANCES:

For employers—Shri Y. C. Sharma.

For workmen-None.

Industry: Stone & Lime District: Satna (M.P.)

AWARD

By an Order No. L-29011/11/71-LR-IV dated 11th May, 1971, the Central Government has referred the following dispute to this Tribunal:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Sutna Stone and Lime Company Limited, Satna in terminating the services of Sarvashri Mahabir Kole (Son of Munda) and Ram Saran Kole (Son of Munda) was justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

Nobody appeared on behalf of the Union although Shri Chander Shekhar Tewari, General Secretary of the Union (M.P. Stone and Lime Mazdoor Sangh) which represented the workmen before the Conciliation Officer had notice of the date *i.e.* 30th June, 1971 fixed in the case for rejoinders and issues and had also been given a copy of the written statement of the employers.

The case was, therefore, fixed for ex-parte evidence on 31st July, 1971 and proceeded ex-parte. Notices which were sent to the workmen themselves, were returned with the remarks that they were not at their houses.

The failure report made by the Conciliation Officer gives the case of the Union in brief. Shri Mahabir Kole was alleged to have submitted an application for 8 days leave on medical grounds on 30th November, 1970. After recovery from illness, he is said to have reported for work on 7th December, 1970 and was not given work. It is also alleged that he submitted an application to that effect to the General Manager on 8th December, 1970 and no reply was given by the management. During discussions with the management, it is said to have been mutually agreed that the workmen shall be taken back on the job and the matter regarding wages was to be discussed subsequently. The workmen had not, according to the Union, been taken on the job. As for Shri Ram Saran Kole, it was alleged by the Union that he reported for duty on 20th October, 1970 after the strike had been called off but was not allowed to join his duties. A written submission alleged to have been submitted to the management on 20th February, 1971 is said to have remained un-replied.

The management denied in the conciliation proceedings that Shri Mahabir Kole had made any application for leave and alleged that he had only remained absent from 30th November, 1970 and has been absent since then. It was denied that he reported for duty on 7th December, 1970 or that any representation was made by him on 8th December, 1970. No demand in respect of Shri Mahabir Kole was, according to the management mutually discussed. As for Shri Ram Saran Kole, the management's case was that he had not reported on duty on 20th October, 1970 and that no representation was received from him. The conciliation proceedings failed although the management was prepared to allow the two workmen employment if they reported for duty within a week. The union insisted for back wages to which the management did not agree.

Before this Tribunal, only the management has filed a written statement, alleging that the Reference is bad in law and beyond the jurisdiction of this Tribunal. The contention is that the Central Government made the Reference without caring to see what the actual dispute was and had pre-judged the matter and taken unwarranted and uncalled-for decision. According to the management, the dispute was whether the management had terminated the services of the workmen and whether they were entitled to back wages, and the Central Government had taken a decision that the management had terminated their services and wanted this Tribunal only to adjudicate whether the termination was justified or not. The management contends that the main dispute was about the question of termination and the Central Government was wholly incompetent to decide it and to make a reference in the form it has done. The reference, according to the management, is wholly invalid. The management's contention is that it had been repeatedly brounght on record and represented that they had never terminated the services of the two workmen and that this would also be apparent from the record note of the joint discussion before the Conciliation Officer and that the management was prepared to allow these workmen employment if they reported for duty within a week and had never refused to provide work to either of them. A copy of letter No. STA/NU/11 dated 25th February, 1971 was also sent to the General Secretary of the Union with the request that he should advise the concerned workmen to report for duty immediately. Notices are also alleged to have been pasted on Notice-Board on 24th October, 1970, 10th November, 1970,

15th November, 1970 and 14th April, 1971, advising the workmen to report for duty. On 29th May, 1971, a registered communication is said to have been sent to the workmen asking them to report for duty before 10th June, 1971 and a copy of this communication is said to have also been pasted on the Notice Board at the mines premises and another copy sent to the General Secretary of the Union. It is further alleged that the dispute, if any, regarding non-employment of these workmen had already been settled by the Conciliation settlement dated 19th April, 1971, said to be still in force. The contention is that according to this conciliation settlement, all disputes relating to any workman upto the date of settlement, had been fully resolved and that there was no valid industrial dispute in existence to confer the requisite jurisdiction on the Central Government to make such a Reference.

On merits also, the management's contention is that even if the management had terminated the services of these workmen, such an action would have been completely justified as the workmen did not report for duty and continued to abstain from work and had been in the past also in the habit of absenting themselves from work without obtaining prior permission or leave of absence.

As held in Delhi Cloth Mills Vs, their workmen: 1967(1) LLJ 423 this Tribunal cannot go beyond the terms of Reference. It cannot, therefore, go into the question whether there was any termination of services or not. It has to proceed on the basis that there was termination of services and decide whether it was or was not justified. That there was an industrial dispute cannot be denied. The union claimed reinstatement and back wages because of termination of their services. The Management agreed to allow them employment but refused to give the back wages. So the Reference is not beyond the jurisdiction of this Tribunal:—

On the date fixed for ex-parte evidence, Shri Y. C. Sharma, Personnel Officer of the management was examined and he stated that from the Attendance Register and the leave account, it will appear that the workmen were absenting themselves. The registers (Exhibits M-6 and M-7) also showed that Mahabir Kole had been shown absent in the register during the period commencing from 1st December, 1970 ending with 31st December, 1970 and was also shown absent in the same register from 1st June, 1971 to 30th June, 1971. Similarly, Ram Saran Kole was shown as absent from 1st May, 1970 to 31st May, 1970 and again from 1st June, 1971 to 30th June, 1971 on all the dates of these months. Shri Y. C. Sharma, (MW-1) also states that the workers absented themselves and were in the habit of absenting themselves. He further states that the workmen themsleves did not come forward in spite of notices and registered letter sent to them and to the Union. It cannot, therefore, be said that there was no justification for termination of their services. They are consequently not entitled to any relief. I make an award accordingly. Lt it be sent to the Central Government. No order as to costs.

(Sd.) M. CHANDRA, Presiding Officer. 31-7-1971

[No. I-29011/11/71-LR-IV.]

S.O. 3381.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore Mines, Chicknayakanahalli owned by Shri P. K. Sarangapani Mudaliar and their workment, which was received by the Central Government on the 25th August, 1971.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

PRESENT:

Shri B. R. Rao, B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 2 OF 1970 (CENTRAL)

Dated Bhubaneswar, the 20th August, 1971.

BETWEEN:

The employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore Mines, Chicknayakanahalli owned by Shri P. K. Sarangapani Mudaliar—First Party.

And

Their Workmen—Second Party.

APPEARANCES:

Shri P. S. Venkatachalam, son of Sri P. K. Sarangapani Mudaliar For the First Party.

Sri Subramani, Sri N. Javaraiah. For the Second Earty.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in its Order No. S.O. 3990, dated 27th November, 1970 as amended in its Corrigendum, dated 16th January, 1971 constituted me as the Presiding Officer, Industrial Tribunal in exercise of powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 and referred the following dispute between the employers in relation to the management of Venkajigudda Iron Ore Mines, Chicknayakanahalli owned by Shri P. K. Sarangapani Mudaliar and their workman.

- "Whether Shri P. K. Sarangapani Mudaliar, 31, Race Course Road, Bangarlore-1, Mines Owner, is justified in denying wages as per. (i). Ist Interim Recommendations, dated the 1st January, 1964; (ii) 2nd Interim Recommendations dated the 1st April, 1966; and (iii) Final Recommendations dated the 1st January, 1967 of the Central Wage Board, for Iron Ore Mining Industry to his workmen employed in his Iron Ore Mines at Venkajigudda, Chicknayakanahalli Taluk, Tumkur District (Mysore State)? If not to what relief are the workmen entitled and from which date?"
- 2. The representatives of the workers filed a written statement alleging that the management is paying each male worker Rs. 2.50 and each famalic worker Rs. 1.50 per day for only 6 days in a week of 7 days. The wages are not paid regularly. The management also did not pay the dues from 9th December, 1969 to 16th January, 1970.
- 3. The management did not file any written statement although is had taken time once to file it. The management, however, contested the Case at the time of hearing.
- 4. Sri P. S. Venkatachalam, the son of Sri P. K. Sarangapani Mudaliar, owner of the Venkajigudda Iron Ore Mines examined himself as M.W. I. On the side of the workmen, one of their representatives Shri N. Javaraiah examined himself as W.W. No. I. From the evidence of M.W. I it transpires that there are approximately 70 workmen (45 males and 25 females) working in the Venkajigudda Iron Ore Mines and that the Management is paying wages of Rs. 2.75 to Rs. 3.25 to each male worker and Rs. 1.50 to Rs. 1.75 to each female worker per day since last 7 or 8 years and it is now prepared to pay Rs. 3 per day to each male worker and Rs. 2 per day to each female worker. The workers are given rent free quarters and free supply of water and these benefits have not been taken into consideration by the management in fixing the wages. As per Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour Remoundations of the Central Wage Board for the Iron Ore Mining Industry, the Venkajigudda Iron Ore Mines can be included in the category of Group I Mines. The minimum total emoluments of the lowest prid unakilled worker in that group should be Rs. 104 per month or Rs. 4 per day including dearness allowance, house rent and other allowances, if any. If the fringe benefits enjoyed by the workers of the Venkajigudda Iron Ore Mines are taken into consideration, the wages which the management is now prepared to pay to these workers are more or less equal to the wages recommended by the Wage Board. Giving reasons why the management could not implement the Wage Board. Giving mendations, M.W. 1 has stated that during the last two years the productivity of the workmen has decreased and the cost of production has gone up from Rs. 3.25 to Rs. 6.50 per tonne and that there is no increase in the purchase price of the ore purchased by the Minerals and Metal Trading Corporation of India Ltd., though the cost of transportation and drilling and blasting has increased. As regards the purchase price, the Government of India in par

Wage Board can be fully implemented without any prejudice to the management. The management, however, cannot withhold implementation of those recommendations on the ground that the purchase price of the ore has not been increased. If the producing capacity of the workmen has decreased, the management can take appropriate action against those workmen. It cannot make that a ground for not giving the benefits of the Wage Board recommendations to the workmen. The Wage Board has taken all circumstances including the financial capacities of the mine owners into consideration in giving the recommendations—final and interim. I do not find any justification why the management should not implement all those recommendations which have been accepted by the Government.

5. Hence I find that Shri P. K. Sarangapani Mudaliar, 31, Race Course Road, Bangalore-I, Mine Owner is not justified in denying wages as per (i) 1st Interim Recommendations, dated the 1st January, 1964; (ii) 2nd Interim Recommendations, dated the 1st April, 1966; and (iii) Final Recommendations, dated the 1st January, 1967 of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry to his workmen employed in his Iron Ore Mines at Venkajigudda, Chicknayakanahalli Taluk, Tumkur District (Mysore State) and that he should implement the recommendations regarding wages without any delay.

(Sd.) B. R. RAO,

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

Dictated & corrected by me.

(Sd.) B. R. RAO,

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneshwar.

[No. 10/40/70-LR-IV.]

New Delhi, the 1st September 1971

S.O. 3382.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudium (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1971.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD PRESENT:

Shri T. Chandrasekhara Reddy, B.A., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

MISCELLANEOUS PETITION No. 18 of 1969

TN

INDUSTRIAL DISPUTE No. 30 of 1967

BETWEEN:

J. S. R. Khabier, General Secretary, A.P.K.K. Union and representative of the Workmen of Singarent Collieries Company Limited, P.O. Ramavaram.

AND

The General Manager, Singareni Collieries Company Limited, P.O. Kothagudem.

Petition, dated Nil filed by the General Secretary, A.P.K. Union and representative of the Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramavaram, under Section 33A of the I.D. Act praying that this Hon'ble Tribunal may be pleased to approve to restore certain facilities such as supply of Free Coffee etc., and for V.D.A.

This application coming on this day for hearing before me and upon persuing the petition counter and upon hearing the arguments of Sri Ramakrishna Rao for the Management and the petitioner being absent, the Tribunal made the following:—

AWARD

Heard Mr. Ramakrishna Rao for the Management. Petitioner is absent though served. The point in issue is in the absence of any authorisation from the aggrieved workmen, whether the Union represented by the General Secretary can file

a complaint under Section 33A of the Act. Sree Ramakrishna Rao relied upon the decision reported in 1954(1) LLJ, page 516, Varuna Ship Builders Ltd., Bombay Vs. Their Workmen and the decision in National Power Supply Corporation Vs. State of Assam and other, A.I.R. 1963 Assam 19, wherein it was held that a complaint under Section 33A must be made by the aggrieved workmen or by the Union with the authority in writing of the aggrieved workmen. In the instant case no such authorisation is filed. No allegation also is made in the petition that the Union had the necessary authorisation in writing to file this complaint. In the circumstances, I respectfully follow the principle laid down in the plaint. In the circumstances, I respectfully follow the principle laid down in the is therefore dismissed as not maintainable.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 31st March, 1971,

(Sd.) T. CHANDRASEKHARA.

Industrial Tribunal. [No. 7/21/67-LRII.]

S.O. 3383.—In pursuanceof of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company Limited, Post Office Rakhikol, District Chhindwara (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th August, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Dated July 7, 1971

PRESENT:

Shri M. Chandra, Presiding Officer.

CASE REF. No. CGIT/LC(R)(9) of 1970

PARTIES:

Employers in relation to the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company, Limited, P.O. Rakhikol, Distt. Chlindwara (M.P.).

Versus

Their workmen represented by (1) Samyuktá Khadan Mazdoor Sangh, Rakhikol (2) M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC) and (3) Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh.

APPEARANCES:

FFor employers-Sri B. C. Sanghi."

For workmen—(1) Sri S. S. Sharma and Sri S. D. Mukherji for S. K. M.

- (2) Sri Gulab Gupta for M. P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh, and
- (3) Sri S. B. Singh for Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh.

INDUSTRY: COAL MINE . DISTRICT: CHINDWARA (M.P.)

AWARD

By an order No. 1/8/70-LRII, dated 22nd July, 1970 the following industrial dispute as given in the schedule attached to that order has been referred to this Tribunal:—

SCHEDULE

- 1. Whether the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company Limited, Post Office Rakhikol, District Chhindwara Is justified in changing the weekly holiday from Sunday to any other day of the week in respect of 250 workmen from August 1969? If not, to what relief are the workmen entitled?
- 2. Whether the termination of employment of Shri Babookhan, Loading Mate by the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company Private Limited, Post Office Rakhikol, District Chindwara, with effect from 1th March, 1969 is justified? If not, to what relief is he entitled,

The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Rakhikol Colliery, gave notice of a loken strike on 8th February, 1970 and a hunger strike from 4th February, 1970 by their letter dated 21st January, 1970 containing a 13 point charter of demands. After considerable discussions a settlement in respect of 5 of the 13 demands was arrived at in the conciliation proceedings. There was no settlement of the remaining demands two of which were demand No. 4 and demand No. 7. Demand No. 4 related to the privilege alleged to have been enjoyed by the workmen of having Sunday as a fixed weekly rest day. The allegation was that the management had changed the weekly rest day of more than 200 workers from Sunday to other days of the week without complying with the provisions of the Mines Act and Section 9A of the Industrial Disputes Act. According to the Sangh the management used to give weekly holidays on Sundays to all the workmen employed in the colliery in accordance with the customs prevalent in the coalfield right from the time the colliery commenced working and continued the practice uninterrupted till July 1969. On enforcement of the Mines Act 1952 on the 1st of July 1952 the management started payment of overtime wages to such workmen as were required to work on Sunday at twice the ordinary rate of wages. It is alleged that the workmen were also allowed a compensatory day of rest on some other day in the succeeding week. The workmen further alleged that the management suddenly changed the conditions of service of 250 workmen illegally with effect from August 1969 by altering the weekly holiday from Sunday to other days of the week and stopping payment of overtime wages to them for working on Sundays. It is alleged that Sunday was observed as a weekly holiday customerily by all collieries in the coalfield so that the colliery workers may have an opportunity of meeting each other to enjoy social life and for purchasing their weekly requirements of food-grains and other necessities from the market which was held only on Sundays. The S

Demand No. 7 relates to Baboo Khan, Loading Mate at the Colliery Siding. During a period of 9 years he is said to have had a clean record of service without any complaint of any misconduct. According to the Sangh, the workman's wife was very sickly and had to be removed for her treatment to welfare hospital several times from January 1969 to March 1969 and the workman attended his duties last on 12th March 1969. It is further alleged by the Sangh that on 13th March 1969 Baboo Khan's wife fell seriously ill and had to be removed to hospital for immediate treatment, that Baboo Khan sent a leave application the very next day through a special messenger for 10 days leave showing his inability to attend to his duties because of the illness of his wife. No orders are said to have been passed on the application. It is further alleged that when the workman reported for duty after the expiry of 10 days leave he was not allowed to resume duty. No charge-sheet is said to have been issued. Nor was any explanation called for, nor a departmental enquiry held. According to the Sangh the services of the workmen were terminated arbitrarily without giving him any opportunity to explain the cause of his absence from duty and the action of the management in terminating Baboo Khan's services is illegal and bad in law and liable to be set aside. The prayer is that Baboo Khan should be reinstated in service with full back wages.

The management contends that the reference is bad in law as it is ambiguous since the names of the two hundred and fifty workmen mentioned therein have not been given. It is also contended that only 90 out of 696 workmen of the Rakhikol Colliery at the time were members of the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh and that the Sangh was not authorised to sepouse the cause of those workmen who were not its members. The reference is alleged to be invalid in so far as those workmen who are not members of the Sangh are concerned. The management urge that the Central Government has not applied its mind to the fact of the case before making the reference to this Tribunal.

On merits, it is alleged that on 5th August 1969 the extraction of coal from No. 18 incline at the top of the hill come to an end, that incline No. 18 was initially abandoned on 8th December 1969 and that a notice of abandonment was sent to the Director General of Mines Safety, Dhanbad on 17th December, 1969 and the mine finally sealed. According to the management, the development of No. 22 incline at the bottom of the hill had started during this period. It is contended that 63 workmen (57 surface trammers and 6 haulage trammers) were rendered surplus as they had no work in No. 22 incline. There were consequently two alternative for the management (1) to retrench these 63 workmen or (2) to accommodate them by giving them some other work. On a suggestion from the Union

to avoid retrenchment that the mine should work on Sunday also and that the day of rest be staggered and changed without waiting for a period of 21 days contemplated by Sec. 9A of the Industrial Disputes Act 1947, the management accepted the proposal in good faith and acted accordingly. It is also pleaded that even when the mine was working for six days in a week and a Sunday was a fixed weekly day of rest for some of the workmen some other categories of workmen, such as Watchmen, Peons, Sweepers, Loco Foreman were not allowed Sunday as their fixed weekly day of rest prior to 1969. It was notified that until further notice the weekly day of rest for each individual was fixed per day as shown against his name in the list. This was to have effect from August 1969. It was, according to the management, a gesture of goodwil intended to promote better employer and employee relations and was appreciated by the unions as such. The management urges that if the weekly day of rest had not been changed for about 200 workmen immediately, about 63 workers would have faced retrenchment and that consequently the action of the management was in accordance with law and was justified. The management pleads estoppel also on the ground that the Symukta Khadan Mazdoor Sangh did not raise any objection till January 1970, and alleged that it was a minority union and had shown by conduct that it was accepted as it was beneficial to the workers. The contention is that whenever the workers have worked on their weekly day of rest the management paid them overtime wages and allowed them compensatory off day and that the workers were consequently not entitled to any relief for working on Sundays.

As for Baboo Khan, it is alleged that from 13th March, 1969 he did not come for work and did not intimate to the management anything about his absence and that consequently on 27th March, 1969 the management issued to him a notice informing him that his name has been struck off from the muster roll on the presumption that Baboo Khan had abandoned the service voluntarily. The noticewas returned to the colliery undelivered with the remark "addressee not traceable". Baboo Khan had been offered in the notice all his legal dues which have not been collected by Baboo Khan. The management contends that the action was in accordance with the Standing Orders and that since no punitive action as contemplated in the Standing Order 17(i) was taken against Baboo Khan it was not obligatory for the management to follow the procedure under Standing Order 17(ii).

After rejoinders had been filed M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh, the Bharatiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh applied for permission to take part in the eproceedings and to file written statements. The management had no objection out the Samyukta Khadan Sangh objected. After hearing the parties at length an order was passed by this Tribunal on 6th October, 1970 allowing M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh and Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh to appear and take part in the proceedings and to file their written statement-cum-rejoinders.

M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh alleged that when the production of coal in Incline No. 18 came to on end in July 1969 and the management served notice upon the union expressing their desire to retrench the surplus workers, the union did not agree to the proposal of retrenchment and that since the development of another incline No. 22 were started near about the same time the Sangh agitation against the proposed M. P. Rashtriya Koyala Khadan retrenchment. According Mazdoor the Sangh, the Management suggested that if the mine could be worked on all the seven days jobs could be found for only 51 persons who were to be retrenched and also 18 others who had already been retrenched. Considering such a proposition in the interest of workers, the Sangh signed a settlement on 2nd August, 1969 agreeing that there would be no retrenchment, that the mine would work on all the seven days of the week and that rest days of the workers would be staggered in accordance with the Mines Act. The contention now is that though the Sangh had agreed to the terms of the settlement the Sangh now finds itself unable to accept the same because of the change in the circumstances since the management has achieved full working of the mine and the production has increased considerably and there does not appear to be any reason for working the mine on all the seven days The Sangh consequently intended to terminate the settlement in accordance with law but there it could be done the reference was made by the Government. This Sangh also consequently joined the other Sangh in its request that the arrangement contained in the settlement of 2nd August, 1969 be done away with and the management should pay wages for overtime rates for all those workers who have been called upon to work on Sundays

In respect of Baboo Khan, M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh alleges that the termination of Baboo Khan's employment was for no valid reasons and that in fact he became a victim of arbitrary behavious of the officers of the company and deserves to be reinstated with full back wages.

The third Sangh, namely, the Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh, also supported the case of the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on both the points.

In its rejoinder the management contends that the change was brought about by the consent of the workers and was for the benefit of the workers, that 21 days notice was not necessary and that the action was justified and legal and was welcomed by the Unions and workers. It is further alleged by the management that the charge in the weekly days of rest of Sunday to other day do not amount to withdrawal of a customary concession and privilege or change in usage and that 21 days notice was not obligatory under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act.

In view of these pleas of the parties a third additional issue was framed as follows:—

Issue

(3) Is the reference bad in law as alleged by the management?

The two items of the schedule in the order of reference were numbered as Issues No. 1 and 2 respectively.

Findings:

Issue No. 3.—There is no vagueness or ambiguity in the order of reference. It is true that the names of 250 workmen are not given in the order of reference but the fact that the names are not given in the order of reference does not constitute any vagueness in the first item of the schedule. It is a case of both the parties that a change was made in the fixed weekly day of rest. The management itself says in its written statement that except for persons like Peons, Workmen, Sweepers, Loco Foreman etc. the mine was working six days in a week and that Sunday was the weekly day of rest for the workmen. Even if the number of workmen, in respect of whom the weekly holiday was changed from Sunday to any other day of the week, be less than 250 it would not make the reference invalid. The main question is that of justification in the change of the weekly holiday from Sunday to another day of the week in respect of a considerable number of workmen from August 1969. If the change was unjustified the workmen would be entitled to a relief and then the question would arise as to what relief they are entitled. There is no ambiguity whatsoever.

Nor is there any question of any ambiguity or vagueness so far as the termination of employment of Baboo Khan is concerned. For the reasons mentioned above the reference is not bad in law.

I find this issue against the management.

Issue No. 1.—The Symukta Khadan Mazdoor Sangh and the management entered into a settlement on 27th February 1971. The M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh objected to that settlement. On 2nd July, 1971 however, the parties present on that day i.e. the management and the M. P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh and the Saymukta Khadan Mazdoor Sangh stated that the settlement dated 27th February 1971 and filed here on the 24th March 1971 may be read with certain modifications mentioned in their statement. They further agreed that they will file a fresh settlement incorporating the aforesaid modifications.

The setflement dated 27th February 1971 and filed on 24th March 1971 here reads as follows:—

Mutual Settlement arrived at under I.D. Act, 1947 between the management of Rakhikol Colliery of S. C. Cambata & Co. and the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on 27th February, 1971 at Chhindwara.

Representing Management

Representing Workmen:

- Mr D.H Wightman, C M.E., Rakhikol I. Shri P. K. Banerjee, Secretry, S. K. M. Colliery.
- Sri S. N. Lal, Manager, Rakhikol
 Sri Akhmtjan, Vice President, S. K. M. Colliery.
 - 3. Sri G.R. Chourasia, Secretry, S. K. Sangh

Short recital of the case

As the concillation proceedings held over the strike notice issued by the S.K.M. Sangh in its notice dated 21st January, 1970 did not result in a settlement, the dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Baboo Khan and restoration of previleges enjoyed by the workmen on Sundays stoppoge of Sunday working) was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the Government of India in their notification No. 1/8/70-LR.II dated 22nd July, 1970. The matter is still before the Hon'ble Tribunal as case No. CGIT/LC(R)(9)/70.

With a view to promoting better relations between the union and the management and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves. In the course of discussions it transpired that the Sunday working was introduced with a view to absorbing the surplus labour consequent on the closure of 18th Incline and with a view to increasing the output. After considerable discussions covering a number of sittings, a settlement acceptable to both parties has been arrived at as follows:-

Terms of Settlement

- 1. It is agreed that on the assurance by the union that they would ensure 7 days' production in 6 days, the management agrees to stop Sunday working with effect from Sunday the 7th March, 1971, it being understood that the usual maintenance work on Sundays will continue as before on the same terms as were obtaining prior to the starting of regular Sunday working.
- Bhri Baboo Khan will be reinstated in his original post with effect from the date on which he reports for duty, treating the intervening period of absence i.e. from the date of dismissal till the date of his rejoining duty as dies non.
- 3. The question of compensation to the workers on account of the Sunday working of the colliery for the period involved as well as compensation to Sri Baboo Khan will be decided by Sri N.K.P. Salve former M.P. in consultation with Sri A.S. Thalati, Director, Sivex C. Cambata & Co. It being understood that in case an amicable settlement is not arrived at within 45 days from the date of this settlement between them, then the ALC(C). Chhindwara would be approached in the matter whose decision to be given within 45 days from the date of the reference of matter to him, will be final and binding on the parties.

In view of the above settlement the union agrees to withdraw the case pending before the Hon'ble Tribunal by filing a copy of this settlement jointly before the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur.

(Sd.) D. H. WIGHTMAN, (Sd.) S. N. LAL,

(Sd.) P. K. BANERJEE, (Sd.) AKHMTJAN.

(Sd.) G. R. CHOURASIA,

Witnesses:

- (Sd.) Illegible.
- 2. (Sd.) Illegible.

The modifications agreed upon between the three parties mentioned above are as follows:-

- "Shri B. C. Sanghi, Shri Gulab Gupta and Shri S. D. Mukherjee state" that the settlement dated 27th February, 1971 and filed here on 24th March, 1971 may be read with the following modifications:-
- In paragraph 1 of the settlement the words "Seven days production in six days" should be substituted by the words "maximum production."
- 2. In paragraph 2 the words "Shri N.K.P. Salve former M.P......binding on the parties" should be substituted by the words "The Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in accordance with the terms of reference."
- 3. The last part of paragraph 3 from "In view......Jabalpur" may be deleted.

Parties present agreed that they would file a fresh settlement incorporating the aforesaid modifications".

On 7th July, 1971 parties filed and verified a modified final settlement which reads thus:-

Mutual Settlement arrived at under I.D. Act, 1947 between the management of Rakhikol Colliery of S.C. Kambata & Co. and the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on 27th February, 1971 at Chhindwara,

Representing Manag ment

Representing Workmen:

- 1. Mr. D.H.Wightman, C.M.E. Rakhikol Colliery,
- Sri P.K. Banerjee, Secty., S.K.M. I. Sangh.
- 2. Shri S.N. Lal, Mafiager, Rakhikol Colliery.
- Sri Akhmatjan, Vice President, S.K.M. Sangh.
- Sri G.R. Choueasia, Secrey. S.K.M.

Short recital of the case:

As the conciliation proceedings held over the strike notice issued by the S.K. M. Sangh in its notice dated 21st January, 1970 did not result in a settlement the dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Baboo Khan and restoration of privileges enjoyed by the workmen on Sundays (stoppage of Sunday working) was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the Government of India in their notification No. 1/8/70-LR.II, dated 22nd July, 1970. The matter is still pending before the Hon'ble Tribunal as Case No. CGIT/LC(R)(9) z

With a view to promoting better relations between the unions and the management and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves. In the course of discussions it transpired that the Sunday working was introduced with a view o absorbing he surplus labour consequent on the closure of 18th Incline and with a view to increasing the output. After considerable discussions covering a number of sittings, a settlement acceptable to both the parties has been arrived at as follows: labour consequent on

Terms of Settlement

- 1. It is agreed that on the assurance by the union that they would ensure maximum production, the management agrees to stop Sunda working with effect from Sunday the 7th March, 1971; it being understood that the useful maintenance work on Sunday will continue as before on the same terms as were obtaining prior to the starting regular Sunday working.
- 2. Sri Baboo Khan will be reinstated in his original post with effect from the date on which he reports for duty, treating the intervening period of absence i.e. from the date of his dismissal till the date of his rejoining duty as dies non.
- 3. The question of compensation to the workers on account of the Sunday working of the Colliery for the period involved as well as compensation to Shri Baboo Khan will be decided by the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in accordance with the terms of reference.

Sd/-(Sd.) D. H. WIGHTMAN

(Sd.) P. K. BANERJEE.

Sd/-(Sd.) Akhmatijan.

(Sdo.) G. R. CHOURASIA.

I agree.

Sd/-(Sd.) GULAB GUPTA Sd/- Illegible. V. Pr. S.K.M.S.

The first clause f the final settlement provides that the management agreed to stop Sunday working with effect from Sunday, the 17th March, 1971, it being understood that the usual maintenance work on Sunday will continue as before on the same terms as were obtained prior to the starting of regular Sunday working. The workmen on their part assured that they would ensure maximum production. This is clearly in the interest of both the workers and the management. While assuring industrial peace it gives to the workers thebenfit of enjoying Sunday as a fixed weekly day except in the case of those who had to do the usual maintenance work. But this also to be continued on the same terms as were in existence prior to the starting of the regular Sunday working. The management stands to gain by the assurance of the workers that they will ensure maximum production.

So far as Baboo Khan is concerned he is also to be reinstated in his original post with effect from the date on which he reports for duty and the intervening period of his absence from the date of his dismissal till the date of his rejoining his duty is to be treated as dies non. This is clearly in the interest of the workman as he is being reinstated to the original post. It is also in the interest of the management since it leads to industrial peace.

As for the question of compensation to the workmen and Baboo Khan it was formerly to be decided by Shri N.K.P. Salve but the parties have now substituted it by the agreement that the question of compensation will be decided by the Central Government Industrial Tribunal. We need not go in the reasons why change was made and what the difficulties were in the way of the partites partly because of the absence of Sri Salve abroad. The whole matter was formerly before This Tribunal for adjudication and this is only a part of the industrial dispute referred to this Tribunal. On a consideration of the entire modified settlement filed and verified on 7th July, 1971 it is clearly in the interest of the workmen and the management.

As for the compensation to the workmen the first question to be decided is whether the change in the fixed weekly day of rest was justified.

The contention of Sri Gulab Gupta for the Union was that the change was illegal inasmuch as no notice under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act was given and that anything illegal is unjustified on the face of it.

Section 9A of the Industrial Disputes Act runs as follows:-

- "9A—Notice of change.—No employer, who propose to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change:—
 - (a) without giving to the workmen likely to be effected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected or
 - (b) within twenty-one days of giving such notice:

Provided that no notice shall be required for effecting any such change.-

- (a) where the change is effected in pursuance of any settlement award or decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950 (48 of 1950); or
- (b) where the workmen likely to be affected by the change are persons to whom the Fundamental and Supplementary Rules, Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, Civil Services (Temporary: Service) Rules, Revised Leave Rules, Civil Service Regulations, Civilians in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules or the Indian Railway Establishment Code or any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the official Gazette apply."

Before Sec. 9A can be applied the change in the conditions of service must relate to a matter specified in the Fourth Schedule. The alleged change is the fixed weekly rest day which was admitted by Sunday before the change. Sri Gulab-Gupta contends that a change in the fixed weekly rest day is covered by items 4, 5 and 8 and relies on a decision of the Patna High Court—Tata Iron & Steel Company Ltd. Vs. Its workmen (1967-I-LLJ 381).

Item 4 of the Fourth Schedule relates to hours of work and rest intervals. The two read together clearly show that the rest intervals mentioned in this item relate to the rest intervals in a day and not rest days of the week or a month. The weekly day of rest would be a rest day in a week and not rest intervals as contemplated by item 4 and is thus not covered by that item. Item 5 deals with leave with wages and holidays. A weekly day of rest may not necessarily be Sunday in any particular concern. The Mines Act does permit staggering of a weekly rest day. Obviously, if the difference days in the week are observed as weekly rest for different workmen it would not be correct to call all the weekly rest days as holidays in the mine. The confusion arises when Sunday is a fixed.

weekly rest day since Sunday is ordinarily regarded as a holiday. As for item No. 8 a weekly rest day is neither a customary concession nor a privilege. It is something to which the workman is entitled under law. Nor can it be said that if Sunday habeen observed as a fixed weekly day of rest in a particular name for a particular period it has become a usage. For usage implies something more than the practice for a few years.

Their Lordships of the Patna High Court have held in Tata Iron & Steel Company case (supra) that a change in the fixed weekly day of rest would be covered by item 4 in the first instance and if not by items 4 and 5 and then by item 8 of the Fourth Schedule. With due respect to their Lordships of the Patna High Court I find myself unable, for reasons mentioned above, to subscribe to that view.

In fact the question arose before the Lordships of the Supreme Court in workmen of M/s. Sur Iron & Steel Company Ltd. Vs. Sur Iron and Steel Company (P) Ltd. [1969(18)F.L.R. 223]. Speaking for the Court Bhargava J. observed:—

"Section 9-A applies to matters enumerated in the Fourth Schedule to the Act. There does not appear to be any specific entry in that Schedule which would cover a condition of service relating to a weekly off-day." (The italicised is mine).

This clearly shows that in the view of their Lordships of the Supreme Court none of the entries in the Schedule Fourth appear to cover the question of weekly off-day.

It was contended on behalf of the workmen that the Supreme Court referred to the notification of the State of West Bengal in the Labour Department and held that the workmen would not be entitled to the benefit of item four of the Fourth Schedule because of that decision and those impliedly held that the weekly rest day was covered by item 4 of the Fourth Schedule. This contention is without force. Bhargava J observed:—

"In the alternative, we can take notice of the contention put forward by the learned counsel for the union before us that the grant of weekly off-day will fall in item 4 of the Fourth Schedule. Even if this submission be accepted, it does not advance the case of the workmen, because the Tribunal specifically found that the Government of the State of West Bengal in Labour Department had issues a notification under Section 9 B of the Act laying down that no notice under Sec. 9-A was required to be served in respect of matters specified in items Nos. 4, 6 and 11 of the Fourth Schedule to the Act for a period of 3 months from the date of publication of the notification in the Calcutta Gazette." (The italicised is mine).

The phrase "even if this submission be accepted" clearly shows that their Lordships of the Supreme Court had not actually accepted the submission that a weekly off-day would fall in item No. 4. This observation will also show that the notification under Sec. 9-B related to only items 4, 6 and 11 of the Fourth Schedule. Consequently, if the question of a weekly rest day was covered by items 5 and 8 as contended by Shri Gulab Gupta the West Bengal Government notification would not have helped the management. In other words, it is clear that the Supreme Court did not consider the question of weekly rest day to be one covered by items 5 and 8 of the Fourth Schedule.

I am therefore not prepared to agree that it was necessary to issue a notice under Sec. 9-A of the Act.

In view of the observations of the Supreme Court in Worknen of Sur Iron and Steel Co.'s case (supra) it is not necessary to consider the second argument on behalf of the management that in Tamilnad Electricity Workers' Federation and another Vs. Madras State Flectricity Board 196.-H-LLJ in 302 Madras High Court) it was held that Sac. 6-A was not designed to present the implementation of any change which is not a change imposed by the employer on the workmen but which is based upon the concent of the workmen to be offered by the employer, the exercise of the judgment with a change was beneficial.

The next contention of Sri Gulan Gupta is that even if the change was not illegal it was not justified. I agree with the learned counsel for the management that the justification was that it avoided the recrenchment of 63 workmen. It is admitted in the written statement filed by the M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh itself, whom Shri Gulab Gupta represents, that the Sangh considered such a preposition (to work the mine for all the seven days) in the interest of the workers and therefore signed a settlement with the management on 2nd

August, 1969 agreeing that there would be no retrenchment of the workers following closure of incline No. 18 and that the mine would be worked on all the seven days of the week and the rest day of the workers would be staggered in accordance with the Mines Act. The other Union contends that it is not bound for whatever was said by the M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh in its written statement. It is true, but it cannot be denied that since the incline No. 18 came to an end, the management had served notices to retrench the surplus workmen. The development of another incline No. 22 had only started then and all the surplus persons could not obviously be employed in the incline No. 22 at that time, if Sunday was observed as a fixed weekly day of rest. The justification for staggering the weekly day of rest was therefore clearly to avoid the retrenchment of the surplus workmen. It may be that merely staggering the weekly day of rest would not provide employment to all the surplus workmen. It is, howexer, in evidence that the suggestion for staggering the weekly day of rest was made and the M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh, representing a considerable number of workmen, agreed to the staggering of the weekly rest day if the workmen were not retrenchment of the surplus workmen. I agree with the learned counsel for the management that this non-retrenchment of the surplus workmen provided a complete justification for staggering the weekly day of rest.

For all these reasons it cannot be said that the change in the weekly day of rest was unjustified. The change was affected only in August 1960 and has in the first quarter of 1971 been modified and Sunday again made a fixed weekly day of rest. Since the change was not unjustified I am unable to hold after the consideration of the entire evidence on record and for the reasons mentioned above, that the workmen are entitled to any compensation.

I find this issue against the workmen so far as compensation are concerned but the terms of the settlement verified on 7th July, 1971 will govern the question of working of the mine on Sundays.

Issue No. 2.—The services of Babookhan have been terminated without any enquiry and without giving him any opportunity to show cause why his services should be terminated. On 27th March, 1969 after his absence since 13th March, 1959 a communciatti. Was rent to him that his name had been truck off from muster roll. In other words, his services had been terminated, Both the parties call it dismissal in the settlement verified on 7th July, 1971. It is true that under the model standing orders absence for more than 10 days is a misconduct. But an action like termination of service for absence amounting to misconduct, an enquiry is necessary under clause 17(ii) of the Model Standing Orders. No enquiry of any kind was held even exparte, and yet the Management terminated the services of Baboo Khan. The termination of his services was therefore unjustified. He has rightly been reinstated now by settlement verified on 7th July, 1971. The notice mentioned in para 7 of the written statement is denid by the workman and it has not been proved that it had been communicated to the workman. There is nothing to show that he was not living in the colliery. The potice was not sent to him by his colliery address and came back to the management unserved. More over, the notice did not ask for his explanation or give him an opportunity to defend himself but merely said that his name had been struck off the rolls. The period during which he was out of service is from 13th March, 1969 till 8th of February 1971. For this period he is antifled to get his full back wages by way of compensation. I find this issue accordingly.

ORDER

As for Sunday working and the reinstatement of Sri Baboo Khan, the reference is decided in terms of the settlement verified on 7th July, 1971, which shall form part of the award. So fer as compensation for staggering the weeking day of rest is concerned, the workmen will not get any compensation. Sri Baboo Khan will get his full back wages from 13th March, 1969 till the date on which he rejoined (i.e. 8th February, 1971) as compensation from the management. I make an award accordingly. In the circumstances of the case parties will bear their own costs. Let the award be set to the Central Government.

Mutual Settlement arrived at under I.D. Act, 1947 between the management of Rakhikol Colliery of S.C. Kambata & Co. and the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh on 27th February, 1971 at Chhindwara.

Representing Management:

1. Mr. D. H. Wightman, C.M.E.,

Rakhikol Colliery.
2. Sri S. N. Lal, Manager,
Rakhikol Colliery.

Representing Workmen:

Sri P. K. Banerjee, Secry., S. K. M. Sangh.
 Sri Akhmatjan, Vice President, S. K. M. Sangh.

3. Sri G. R. Chourasia, Secrey., S. K. M. Sangh,

Short recital of the case

As the conciliation proceedings held over the strike notice issued by the S.K.M. Sangh in its notice dated 21st January, 1970 did not result in a settlement, the dispute regarding the alleged wrongful dismissal of Sri Babookhan and resotration of privileges enjiyed by the workmen on Sundays (stoppage of Sunday working) was referred to the Central Government Industrial Tribunal at Jabalpur by the Government of India in their notification No. a/8/70-LR II dated 22nd July, 1970. The matter is still before the Hon'ble Tribunal as case No. CGIT/LC(R)(9)/70.

With a view to promoting better relations between the union and the management and as a gesture of mutual goodwill the parties started discussions and negotiations mutually with a view to arriving at a settlement amongst themselves. In the course of discussions it transpired that the Sunday working was introduced with a view to absorbing the surplus labour consequent on the closure of 18th Incline and with a view to increasing the output. After considerable discussions covering a number of sittings, a settlement acceptable to both the parties has been arrived at as follows:-

Terms of settlement

- 1. It is agreed that on the assurance by the union that they would ensure maximum production, the management agreed to stop Sunday working with effect from Sunday the 7th March, 1971; it being understood that the usual maintenance work on will continue as before on the same terms as were obtaining prior to the starting of regular Sunday working.
- 2. Sri Babookhan will be reinstated in his original post with effect from the date on which he reports for duty, treating the intervening period of absence i.e. from the date of his dismissal till the date of his rejoining duty as dies non.
- 3. The question of compensation to the workers on account of the Sunday working of the Colliery for the period involved as well as compensa-tion to Shri Baboo Khan will be decided by the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in accordance with the terms of reference.

Signature of the parties:

Sd/- D. H. WIGHTMAN

Lagree Sd/- GULAB GUPTA

Sd/- P. K. BANERJEE Sd/- G. R. CHOURASIA Sd/- SKHMATJAN Sd/ Illegible. V. Pr. S.K.M.S.

Filed by Sri B. C. Sanghi and verified on behalf of the Management by Sri B.C. Sanghi, identified by Sri Gulab Gupta, Advocate and also verified by Sri Gulab Gupta, Advocate for M. P. Koyla Khadan Mazdoor Sangh, and by Sri G. R. Chourasia (identified by Sri B. C. Sanghi) for the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh.

Sd/- M. CHANDRA, 7-7-1971.

\$d/- B. C. SANGHA Sd/- GULAB GUPTA

Sd/- G. R. CKOURASIA

Part of Award Sd/- M. CHANDRA Presiding Officer.

[No. 1/8/70-LRII.]

ORDERS

New Delhi, the 28th June 1971

S.O. 3384.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Balihari Colliery of Messrs.

Balihari Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda,
District Dhanbad, in dismissing Shri Prabhu Ram Night Guard, from
service with effect from the 29th July, 1967, is justified? If not, to
what relief the workman is entitled?"

[No. L/2012/69/71-LR.II]

(श्रम श्रीर रोजगार विभाग)

ग्रा वेदा

नई दिल्ली, 28 जन, 1971

का॰ जा॰ 3384.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुस्वी में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बिलहारी कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुसन्दा, जिला धनबाद की बिलहारी कोलियरी के प्रबन्ध में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक भौग्रीगिक विषाद विद्यमान हैं:

े और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन वे लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

श्रतः, श्रव, श्रौद्योगिक विनाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 का उपधारा (1) के खाड (घ) द्वारा प्रत्न शिक्ष्यों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त श्रीधिनियम की धारा 7क के श्रधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रीक्ष-करण (संख्या 1), धनवाद के न्यायिन्णेयन के लिए निर्देशित वस्ती है।

प्रनस्ची

"क्या मैसर्म बिलहारी कोशियरी वस्पनी प्राष्ट्रवेट लिमिटेड, डाकघर कुसुन्दा, जिला धनबाद की बिलहारी कोलियरी के प्रबन्ध मंडल की श्री प्रभु राम, नाइट गार्ड, को 29 जलाई, 1967 में मेवा से बरखामा करने की कार्यवाही न्यायोजित हैं ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[मं॰ एल०/2012/69/71-एल०मार०-2]

New Delhi, the 2nd July 1971

S.O. 3385.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri K. V. Kollali, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore;

And, whereas, the services of Shri R. V. Kollali have ceased to be available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and subsection (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Narayan Rai Kudoor as the Presiding Officer with headquarters at Bangalore, withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Shri R. V. Kolali and transfers the same to the said Industrial Tribunal, Bangalore, for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sr. No. Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial dispute	S.O. of G ₁₂ zette/ Year of Publication
 Management of Messrs, Mine- rals Sales (Private) Limited, Mine Owners, Hospet their contractors on Vyasanakere Iron Ore Mine & their workmen. 	No. 10(42)/70-LR-IV, dt. 18-11-1970	387x of 19 7 0

[No. L-29025/14/71-LR-IV.]

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1971

का०म्रा० 3385.-यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रौद्योगिक विवाद, श्री के० बी० कोल्लाली, पीठासीन श्रधिकरी, औद्योगिक श्रधिकरण, बंगलीर के समक्ष लम्बित है ;

भौर यत: श्री भ्रार० बी० कोल्लाली की नेवाएं उपलब्ध नहीं रहीं ;

श्रतः, श्रव, श्रोंद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क श्रोर 33ख धारा की उनधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक श्रीद्योगिक श्रिधकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रिधकारी नारायण राय कुदूर होंगे, जिनका मुख्य कार्यालय बंगलौर होगा, श्री श्रार० बी० कोल्लाली से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को वापिस लेती है श्रौर उसे उक्त कार्यवाही के निपटान के लिए उक्त श्रीद्योगिक श्रिधकरण, बंगलौर को इस निदेश के साथ स्थानातरित करती है कि उक्त श्रीधकार श्रौर श्रागे कार्यवाही उस प्रकम से करेगा जिसे वह उसे स्थानातरित की जाए श्रौर विधि के श्रनुसार उसका निपटान करेगा,

श्रनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	श्रोद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या श्रौर तारीख	राजपत्न में का० धा ० प्रकाशन का वर्ष
1	मैंस्सं मिनन्त्स सेत्स (प्राइवेट) लिमिटेड माईन श्रोनर्स, होस्पेट के प्रबन्ध व्यासना केरे श्रायरन श्रौर माइन में उनके ठेकेंदार तथा उनके कर्मकार	संख्या 10(42)/70 एल० श्रार०—4, तारोख 18— 11—1970	1970 का 3871

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 3386.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the managment of Dhansar Colliery of Messrs The Pure Dhansar Coal Company. Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Scheule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) or section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dhansar Colliery of Messrs The Pure Dhansar Coal Company, Post Office Dhansar, District Dhanbad, in stopping Shri Rabindra Nath Biswal, Attendance Clerk from work with effect from the 15th February, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L. 2012(88)/71-LRII.]

नई दिल्ली, 6 ज्लाई, 1971

का० ग्रा० 3386 — यतः केन्द्रीय गरकार की राय है कि इसमे उपाबद्ध ग्रनुसूची में विनिर्दित्य विषयों के बारे में भैंसमें वि प्योर धनसार कोल कम्पनी, डाकधर धनसार, जिला धनबाद की धनसार कोलियरी के प्रबन्ध में सम्बद्ध नियोजको ग्रौर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती हैं ;

अत:, श्रब, श्रौद्योगिक विवाद श्रीधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करने हुए, वेन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उवत विवाद को उक्त श्रिधिनियम की धारा 7-क के श्रधीन गटिन केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रिधिकरण (संख्या) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देणित करनी है।

ग्रनुसुची

"क्या मैसर्स दि प्योर धनसार कोल कम्पनी, डाकघर धनसार, जिला धनबाद की धनसार कोलियरी के प्रबन्ध मण्डल की श्री रवीन्द्रनाथ विश्वाल, हाजिरी क्लर्क को 15 फरवरी, 1971 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस श्रनुतोष का हकदार है ?

S.O. 3387.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pure Jeyramidh Colliery of Messrs Pure Joyramdih Colliery Company, Post Office Nudhurkee, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Pure Joyramdih Colliery of Messrs
Pure Joyramdih Colliery Company, Post Office Nudkhurkee, District
Dhanbad, In stopping Shri Shambhu Nath Mishra, Mining Sardar from
work with effect from the 23rd October, 1970, is justified—If not, to
what relief is the workman entitled?"

[No. L-2012/91/71-LR.II.]

कार ग्रांत 3387. -- यत. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिद्धिट विषयों के बारे मे मैं मर्स प्योर जोयरामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर नृदखुर्की, जिला धनबाद की प्योर जोयरामडीह कोलियरी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजको ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रौर यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है :

ग्रतः, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त श्रिधिनियम की धारा 7-क के श्रिधीन संगठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रिधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

ग्रन्स् ची

"क्या मैंसर्स प्योर जोयरामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर नुद्खुर्की, जिला धनवाद की प्योर जोयरामडीह कोलियरी के प्रबन्धमंडल की श्री शम्भुनाथ मिश्र, खनन सरदार की 23 श्रक्तूबर, 1970 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोजित हैं ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस श्रनतीप का हकदार है ?

[सं० एल० 20 1 2/9 1/ 7 1- एल**०** यार०-2]

New Delhi, the 21st July 1971

S.O. 3388.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed pending before Thiru S. Swamikkannu, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras:

And whereus the services of Thiru S. Swamikkannu have ceased to be available:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and subsection (1) of section 33B of the Industrial Dispute; Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru Seetharama Rao as the Presiding Officer, with headquarters at Madras, withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Thiru S. Swamikkannu, and transfers the same to the said Industrial Tribunal, Madras, for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

S1. No.	Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial Tribural	S.C. No. if Gazette Year of Publication
<u>, I</u>	Management of Oil and Natural Gas Commission Karaikkal and their workmen.	7 5), 70-I.R-IV dated 27-2-71	1071 71

नई दिल्ली, 21 जुलोई, 1971

का॰ धा॰ 3388---यतः इससे उपाबद्ध प्रतुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रौद्योगिक विवाद थिरु एस॰ स्वामीकन्तु, पोठासीन श्रधिकारी, ग्रौद्योगिक श्रधिकरण, मद्रास के समक्ष लिखत है ;

भीर यतः थिरु एस० स्वामीकन्तु की सेवाएं उपलब्ध नहीं रही है ;

श्रतः, श्रव, श्रीयोगिक विवाद श्रिविनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क श्रीर धारा 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा एक श्रीयोगिक श्रिविकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रिविकरी थिक सीथारामा राव होंगे, जिनक मुख्यालय महास होगा, यिक एस० स्वामोकञ्च से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को वापिस लेती है श्रीर उसे उक्त कार्यवाही के निपटान के लिए उक्त श्रीयोगिक श्रिविकरण, मद्रास को इस निवेश के साथ स्थानांतरित करती है कि उक्त श्रिविकरण श्रीर श्रागे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर उसे स्थानांरित की जाए श्रीर विधि के श्रनुसार उसका निपटान करेगा।

भन्मुची

ऋम सं०	विवाद के पक्षकार	श्रोद्योगिक श्रधिकरण की निर्देश संख्या श्रोर तारी ख	राजपन्न में आरा० ग्रार०स०		
			पकाशन का वर्ष		
1	तेल स्रोर प्राकृतिक गैस स्राप्नोग, कराय- वकल _, त्रीर उनके कर्मकार	7(5)/70-एल०म्रार०, IV तारीख 27-2-71	7 1071/71		
		[संख्या 7 (5) / 7	0 - एल० ग्रार० ▲]		

[संख्या 7(5)/70-एल० श्रार**० 4**]

New Delhi, the 23rd July 1971

S.O. 3389.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Bikaner Gypsum Limited, Bikaner and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes and Industrial Tribunal with Shri Gopal Narain Sharma, as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the claim of the Bikaner Gypsum Mazdoor Union Bikaner that the Drillers and Auto Electric Attendants of the Bikaner Gypsum Limited, Bikaner should be supplied with woollen uniforms is justified? If so, at what scale and from which date?

[No, L-25011/3/71-LR-IV.]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1971

का० आ० 3389,यतः केन्दीय सरकार की राय है कि उससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, बीकानेर के प्रबन्ध से सबम्द्ध नियोजकों और उनके कर्षकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद बिग्रमान है ;

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है

अत:, श्रब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भौर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत बारा एक औद्योगिक ग्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रधिकारी श्री गोपाल नारायण शर्मा होंगे, जिनका मख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त ग्रीद्योगिक ग्रधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

प्रन्सुची

"क्या बीकानेर जिप्सम मजदूर यूनियन बीकानेर का यह दावा न्यायोचित है कि बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के डिलरों भ्रौर स्वत: विजली परिचरों को गर्म विदयां सप्लाई की जानी चाहिएं ? यदि हां, तो किस स्केल पर श्रोर किस तारीख से ?

[सं॰ एस॰-25011/3/71-एल धार-4]

New Delhi, the 30th July 1971

the Central Government is of opnion that an industrial dis-**S.O**: **3390.**—Whereas pute exists between the employers in relation to the management of Messrs R. K. Schant and Sons (Private) Limited, Post Office Kodarma Distitrict Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for djudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs R. K. Sahana & Sons (Private) Limited, Post Office Kodarma is justified in terminating the services of the following workers of Bhadiya Mica MinerKodarma area)? If not what relief they are entitled to?"

Name of the workmen

- Shri Bahun Gope (Shrt Firer)
- Chottu Gope (Fitter)
- Bhikhan Barhi (Carpenter) 3-
- Tejan Barhi (Blaster)
- " Rolpan Barhi (Baniyati) " Ganpat Bahri (Baniyati)
- 7· 8. Fagun Das (Baniyati)
- Lachu Gope (Baniyati)
- " Itwari Barhi (Dhari) 9. " Har Lal Gope (Dhari) 10.
- II. ,, Narayan Hazam (Dhari)
- " Banwari Hazam (Dhani) 12.
- " Chaman Gope (Dhari)
- 13. Kecar Barhi (Dhari)
- 14.
- " Depan Chamar (Dhari) 15.
- " Prabhu Chamar (Surface) 16.
- 17. " Noonman Gope (Dhari)
- " Noor Md. Mia (Dhari) 18.
- Sukha Singh (Dhari) 19.
- " Birjuram (Dhari) 20.
- " Bahram Gope (Dhari) 21.
- " Dharam Gope)Dhari) 22.
- 23. Radha Das (Dhari)
- Bansi Hazam (Dhari) 24. 33
- Mangal Barhi (Dhari) 25.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1971

का० ग्रा० 3390.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में विनि-विष्य विषयों के बारे में मैसर्स ग्रार० के० साहाना एण्ड सन्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कोडमी, जिला हजारीबाग के प्रबन्धमंडल से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

श्रत:, श्रव, श्रांद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्द्वारा अक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-कं के श्रधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण (संख्या 1), धनवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

श्रनुसूची

"क्या मैंसर्स ग्रार० के० साहाना एन्ड सन्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कोडर्मा के प्रबंधमंडल का भादिया माइका माइन (कोडर्मा) क्षेत्रों के निम्नलिखित श्रमिकों की सेवाएं समाप्तः करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस श्रनुसोष के हकदार है ?

कर्मकारों के नाम

1-श्री बावन पोप (शट फायरर)

2-श्री छोट्ट गोप (फिरटर)

3-श्री भिषान बाहीं (बढ़ई)

4-श्री तेजन बाहीं (बर्ई)

5-श्री रोल्पान बाहीं (बनियाती)

6-श्री गणपत बाहीं (श्रोपरि)

7-श्री काल्गुन दास (यथोक्त)

8-श्री लच् गोप (यथोक्त)

9-श्री इतवारी वाहीं (धारी)

10-श्री हर लाल गोप (धारी)

11-श्री नारायण हाजम (धारी)

12-श्री बनवारी ह जम (धारी)

13-श्री चमन गोप (धारी) 14-श्री केदार बार्ही (धारी)

15-देपन भ्रमार (धारी)

16-प्रभा चमार (सतह)

17-श्री नुनमान गोप (धारी)

18-श्री नूर महम्मद मियां (धारी)

19-श्री मुखा सिंह (धारी)

20-श्री बिन्जुराम (धारी)

21-श्री बर्हाम गोप (धारी)

22.-श्री धरम गोप (धारी)

23.-श्री राधा दास (धारी)

24.-श्री बसी हाजम (धारी)

25.-श्री मंगल बाहीं (धारी)।

[सं० एस०-28012/2/71-एल श्रार-4]

S.O. 3391.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bisrampur Colliery of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Bisrampur Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

"Whether the termination of scrvices of Shri Shyamanand Shukla, Ex-Armature Winder (Regional Workshop), Bisrampur Colliery of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Bisrampur Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh) by the management of Bisrampur Colliery with effect from the 20th November, 1968 is justified? If not, to what relief Shri Shukla is entitled?"

[No. L/2212/6/71-LRII.]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

का० ग्राँ० 3391.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल कोल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, डाकघर विसरामपुर कोलियरी, जिला मुर्गुजा (मध्य प्रदेश) की विसरामपुर कोलियरी के प्रवन्ध से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उनके कर्म-कारों के बीच एक ग्रीद्योगिक विवाद विद्यमान हैं;

ग्रीर यत[.] क्रेन्द्रीय सेरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

श्रतः, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधित्यम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सेरकार एतद्द्वारा उक्त विवार को उक्त ग्रिवित्यम की धारा 7-क के श्रधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रधिकरण, जबलपु को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

ग्रनुसूची

"क्या विसरामपूर कोलियरी के प्रबन्ध मंडल द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड् डाकघर बिसरामपूर कोलियरी, जिला सुर्गुजा (मध्य प्रदेश) की विसरामपुर कोलियरी के भूतपूर्व प्रामचिर वाइन्डर श्री श्यामानन्द णुक्त की 20 नवम्बर, 1968 से सेवा समाष्ति न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो श्री णुक्त किम ग्रनुतोद का हकदार है ?

[मं० एल-2212/6/71-एलग्रार-2]

धार० कुंजीयापदम, श्रवर सचित्र।

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Délhi, the 20th August 1971

S.O. 3392.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bombay Harbour Transport Company, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Bombay Harbour Transport Company, bonus for the year 1969-70, is justified? If not, what should be the quantum of bonus for the said year?"

[No. L. 31013/2/71-P&D.]

(अम श्रीर रोजगार विभाग)

श्चादेश

नई दिल्ली, 20 ग्रगस्त, 1971

का० श्रा० 3392.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध श्रनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बोम्बे हार्बर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मुम्बई के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों श्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीद्योगिक विवाद विद्यमान है;

भ्रौर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निद्यागित करना वांछनीय समझती है;

ग्रतः, श्रब, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त श्रिधिनियम की धारा 7-क के श्रधीन गठित केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक श्रिधिकरण, मुम्बई को न्याय-निर्णयन के लिए निर्दाशत करती है।

ग्रनुसूची

"नया मेसर्स बोम्बे हार्बर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मुम्बई-1 के प्रबन्ध मण्डल के कर्मकारों की, 1969-70 वर्ष के लिए 20 प्रतिशत बोनस की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उन्त वर्ष के लिए बोनस की माता कितनी होनी चाहिए ?"

[सं० एल-310132/71-पी एण्ड डो]

New Delhi, the 27th August 1971

S.O. 3393.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen represented by the National Union of Waterfront Workers, Calcutta;

And whereas the said employers and their workmen have, by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

AGREEMENT

[Under Section 0A of the Industrial Disputes Act, 1947]

Name of the parties:

Representing Employers—Shri T. R. Rgahupathi, Secretary, Commissioner for the Port of Calcutta.

Respresenting Workmen-Shri Janki Mukherjee, General Sccretary, National Union of Waterfront Workers

It is hereby agreed between the perties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri B. K. Jayarama Rao, Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta:

- (i) Specific matters in dispute.—Whether the claim of Shri R. N. Saha, Lascar, for promotion to the post of Seacunny on M. L. "Investigator" is justified?
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.—The Employers in relation to the Commissioners for the Port of Calcutta, 15, Strand Road, Calcutta-1 and their workmen represented by the National Union of Waterfront Workers, 10, Mohan Chand Road, Calcutta-23.
- (iii) Name of the Workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workmen in question.—National Union of Waterfront Workers, 10, Mohan Chand Road, Calcutta-23.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected— 42,000 approximately.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.—2.

The Arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing Employers-

Signature of the Parties.
Sd./- T. R. RAGHUPATHI,
Secretary.
Commissioner for the Port of Calcutta.

Representing Workmen-

Sd./- JANARI MURHERJEE,
General Secretary,
National Union of Waterfront Workers.

Witnesses:

- (i) Sd/- N. D. CHARRABORTY, Jr Asstt Secretary, C.P.C.
- (ii) Sd./- HITEY Roy, Secretary, NU.W.W.

[No L-32014/3/71-P & D.]
O. P TALWAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 धगस्त, 19**7**1

का • आर. 3393 -- एक का का पतान आयक्त कला को नियोजकों और उस के वर्षकारों, जिनकां प्रतिनिधिक ने पान प्रियन याँक बाटरफल्ट वर्षमें करती है, के बीच उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक भौगोजिक विकाद विद्यास है :

पौर एक उरत कि को भीर उन के कर्मकारों ने पौपोगिक विवाद पश्चिनियम. 1947 (1947 का 14) की भारा 10क की उक्षाक (1) के स्थीत विखित करारद्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यमस्थम् करार की एक प्रति उक्त प्रधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के प्रधीन केन्द्रीय सरकार को भेषा दी है;

ग्रतः, श्रव , उक्त श्रधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के श्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त करारको एतद्दारा प्रकाशित करती है ।

करार

(श्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 19क के श्रधीन)

पक्षकारों के नामः

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

श्री टी० ग्रार० रद्यपति, सचित्र , कलकत्ता पत्तन वे लिए ग्रायुक्त ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

श्री जानकी मुकर्जी, भहा सचिव, नेणनल यूनियन श्राफ बाटरफ्रन्ट वर्क्स।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित आँद्यागिक विवाद को एतद्द्वारा श्री बी० के० जयारामा राव, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता के माष्ट्यस्थम् के लिए निर्देणित करने का करार किया गया है ।

- (i) विनिद्धिष्ट विवादग्रम्त विषय
- क्यार्थी श्राप्० एन० माहा, लक्कर का, एम० एन० ''श्रन्वेषक'' पर सीकक्षी के पद पर प्रोन्नति के लिए दावा 'यायोचित हैं?
- (ii) विवाद केपक्षकारों का विवरण जिस में श्रन्तर्विलित कलकत्ता के पत्तन के लिए श्रायुक्त ,, स्थापन या उपक्रम का नाम और पना भी 15, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1 से सम्मिलित है। सम्बद्ध नियोजकों श्रीर उन के कर्म-
 - कलकत्ता के पत्तन के लिए श्रायुक्त ,, 15, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1 से सम्बद्ध नियोजकों श्रीर उन के कर्म-कार जिनका प्रतिनिधित्व नेशनल यूनियन श्राफ वाटरफन्ट वर्कर्स, 10, मोहन चन्द रोड, क्लकत्ता-23 करतों है।
- () यदि कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्वेशित है तो उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार का प्रतिनिधित्य करता हो तो उसका नाम ।
- नेशनल यूनियन श्रांफ वाटरफन्ट वर्कर्स , 10, मोहन चन्द रोड, कलकत्ता-23
- (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल लगभग 42,000 संख्या ।

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या । 2

मध्यस्थ भ्रपना पंचाट छः मास की श्रवधि के भीतर या इतने श्रौर समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि ऊपर विणित श्रवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा श्रौर हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

ह०/- टी० भ्रार० रघुपति, सचिव, कलकत्ता के पत्तन के लिए भ्रायुक्त

कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले

ह०/- जानकी मुखर्जी, महासचित्र, नेशनल यूनियन श्रौफ वा रफ्रन्ट वर्कर्स ।

साक्षी:

- (i) ह० एन० डी० चक्राबोर्ती, कनिष्ठ सहायक, सचिव, सो० पी० सी०
- (ii) ह०/- हितेनराय, सचिव, ने०य०वा०व०

[सं० एल $-3201\ 4/3/71$ -पी० एण्ड डी०]

स्रो० पी० तलवाड्, उप स[ि]चव ।

(Department of Rehabilitation) (Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 18th August 1971

S.O. 3394.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to acquire the Evacuer Properties specified in the schedule hereto annexed in the States of Delhi, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Kerala, Rajasthan and Uttar Pradesh, for a public purpose being a purpo e connected with the relief and rehabilitation of displaced persons including payment of compensation to such persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (44 of 1954), it is notified that the Central Government, has decided to acquire and hereby acquires the evacuee properties specified in the schedule hereto annexed.

A SCHEDULE

All properties in the States of Delhl, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Kerala, Rajasthan and Uttar Pradesh which have been allotted to the share of the Custodian in partition or have been vested in the Custodian under section 11 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, as a result of adjudication by the Competent Officer under the provisions of the said Act upto 30th June, 1971, and in respect of which appeals have not been filed, and if filed, have been rejected by the Appellate Officer.

[No. 29(2)/Comp. & Prop/71.]

JANKI NATH.

Settlement Commissioner and Ex-Officio, Under Secy.

(पनवींस विभाग)

मस्य बन्दे,बस्त श्रायुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली 18 श्रगस्त, 1971

एस० मो० 3394.—यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, जडीसा, पंजाब, हिरयाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, श्रान्ध प्रदेश, तामिलनाडू, मैसूर, केरल, राजस्थान प्रोर उत्तर प्रदेश राज्यों मे स्थित निष्कान्त सम्पत्तियों का, जो अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट की गई हैं, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए श्रजंन करना ग्रावश्यक है। इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास से है श्रीर इस में ऐसे व्यक्तियों को मुशावजे का भुगतान करना भी शामिल है। ग्रतः ग्रब विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) ग्रिधनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 12 में प्रदत्त शर्वाय प्रयोग करने हुए यह श्रिधसृचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रजंन का निर्णय कर लिया है श्रीर इसके द्वारा अनबद्ध श्रनुसूची मे निर्दि ट निष्कान्त सम्पत्तियों का श्रजंन करती है।

ग्रनसूची

दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिह र, उडीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, श्रान्ध्र प्रदेश, तामिलनाडू, मणूर, जेरल राजस्थ न और उत्तर प्रदेश राज्यों में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में श्रिभ-रक्षफ के हिस्से में श्रावित की गई ८ या निष्काल हित (पार्थक्य) श्रधिनियम, 1951 की धारा 11 के ग्रधीन सक्षम श्रधिकारी के न्याप निर्णय के परिणामस्वरूप नित्त श्रधिनियम की धाराश्रों के ग्रन्तगैत 30-6-71 तक ग्रभिरक्षक के ग्रधिकार में रही शौर जिनके बारे में कोई श्रपील दायर नहीं की गई है भौर विद की गई हो तो उन्हें अपील श्रधिकारी द्वाण रह कर दिया गया हो।

सख्या 29(2)/कम्प० एण्ड प्रोप*ः*/71]

जानकी नाथ,

बन्दोबस्त श्रायकत तथा पदेन श्रवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 27th August 1971

S.O. 3395.—In exercise of the powers conferred the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companie of Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Central Galanment hereby appoints Shri A. K. Dutt, Joint Secy. Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a member of the First Board of Directors of the Punjab National Bank in place of Shri A. T. Bambawale, with immediate effect.

[No. 2(13) PSB-NB/71.] D. K. SEN, Under Secy.

वित मंत्रालय

(बैंकिंग जिभाग)

नयी दिल्ली, 27 ग्रगस्त, 1971

एसं आं 3395.—बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवा) की धारा 7 की उपधारा (3) खंड (क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बैंकिंग विभाग, वित्त मैदालय, नयी दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री ए० के० दक्त की श्री ए० टी० बम्बेवाले के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक के प्रथम निवेशक वोर्ड का सदस्य तत्काल निय्क्त करती है।

[सं० 2(13) पी० एस० बी०-एन० बी०/71.]

डी० के० सेन, ग्रवर सचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 22nd July 1971

S. O. 3396.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 16th July, 1971

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	22,56,52,000 3,33,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,77,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.	190 ,00,00, 000	(a) Internal	8,73,12,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	39,00,00,000		28,76,17,000 123,85,79,000
		Investments**	240,23,27,000
Vational Industrial Credit (Long Term Operations) Fund .	135,00,00,000		 117,19,03, 00 0
Deposits:—		(, - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210,62,85,000
(a) Government (i) Central Government	55,24,5 5,00 0	(ii) State Co-operative Banks††	194,96,72,000 4,61,84,000
(ii) State Governments	4,02, ₇ 6,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultura Credit (Long Term Operations) Fund	1
(b) Banks		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	208,58,07, 000	(i) State Governments.	42,03,56,00
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	11,20,09,000	(ii) State Co-operative Banks	23,80,92,00
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	81,17,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	
(iv) Other Banks	37,73,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.	10,14,98,00

(c) Others .	•	•	•	•	٠	•	•	•	154,34,38,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks, Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund. 14,14,37,000
Bills Payable		•		•			•		41,70,73,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank
Other Liabilities									150,77,66,000	ment Bank
			Ru	ıp ces	•		•	•	1146,07,14,000	Rupees 1146,07,14,000

^{*}Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

Dated the 21st day of July, 1971.

S. JAGANNATHAN, Governor.

^{**}Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State

Governments.

+Includes Rs. 147,01,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

[†]Includes Rs. 147,01,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural (Stabilisation) Fund.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 16th day of July 1971.

Teetir DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department. Notes in circulation Total Notes issued	. 22,56,52,000		Total	. 182,53,11,000 243,42,00,000	425,95,11,000
			Rupee Coin Government of India Rupee Securities Internal Bills of Exchange and other commercial paper	· ·	39,64,38,000 3982,94,32,000
TOTAL LIABILITIES	••	4448,53,81,000	TOTAL ASSETS		4448,53,81,000
Dated the 21ts day of July, 1971.				(Sd.) S. Jag.	ANNATHAN. Governor.

[No. F.3(3)-BC/71]

(बॅकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1971

एस॰ ग्रो॰ 3396 -- 16 जुलाई 1971 को रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया के वैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं			रु पये	भ्रा	स्तिया		रुषये
कृता पूंजी .			5,00,00,000	नोट .			22,56,52,00
गरक्षित नि धि .	, -		150,00,00,000	रुपये का सिक्का .	,		3, 3 3, 0 0
				छोटा सि क् का .		•	3,77,00
ष्ट्रीय ऋषि ऋण							
दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि			190,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल:			
तष्ट्रीय कृषि ऋण			·	(क) देशी .			8,73,12,00
स्थिरीकरण) निधि			39,00,00,000	(खं) विदेशी		•	
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '				(ग) सरकारी खजाना बिल			28,76,17,00
ष्ट्रीय श्रौद्योगिक ऋण				विदेशों में रखा हुग्रा बकाया*	,		123,85,79,00
दीर्घकालीन कियाएं) निधि			135,00,00,000	निवेश**			240,23,27,00
भाराशियाँ:				ऋण ग्रौर भ्राग्निम			
क) सरकारी				(i) केन्द्रीय सरकार को			
(i) केन्द्रीय सरकार			55,24,55,000	$(\ddot{\mathbf{i}})$ राज्य सरकारों को $@$			117,19,03,00
ii) राघ्य सरकार		,	4,02,76,000	ऋण ग्रौर ग्रग्निमः			
ख) बेंक				(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंको	ांको † .		210,62,85,00
(i) ग्रनुसूचित वाणिज्य बैंक			208,58,07,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों क			194,96,72,00
ii) प्रतुसूचित राज्य सहकारी बैंक			11,20,09,000	(iii) दूस रों को			4,61,84,00
/ 46 2				रोष्ट्रीय क्रुंषि ऋ ष (दीर्घकार्ल	नि कियाएं)	निधि से	
				ऋण, अग्रिम और निवेश	-,		

ST.	4
IJ.	- 3
11	×
U	
ă.	-
!	Ξ
П	Ĺτ
ĮĮ.	C
Ш	⊳
Ħ	2
Ш	5
Ш	L
il	Ü
11	
Н	¥
11	_
Ш	Z
3	U
1	-
₩	
	CO.
И	Ū
IJ.	3
	7
Ш	€
Ш	Ĥ
П	H
ļl.	×
	_
21	
Ш	<u> </u>
[[. 9
il .	7
il .	\rightarrow
И.	3
li -	5
li -	Н
1	×
[]	5
H	'n
11	Ö
!	_
ll I	00
<u> </u>	93
l	
il	6 THE GAZETTE OF INDIA; SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20, 1893 [P.
	PART II-
Ш	Ħ
	7
W.	Ħ
!	1.

एस**ः ज**ान्नाथन,

गवर्नर ।

	देयताए		-	रुपये	ग्रास्तियां			रुपये
		· · · ·			(क) ऋण और अग्रिमः—			
(iii) गैर अनुसूचित	राज्य सहकार	ते बैंक		81,17,000	(\mathbf{i}) राज्य सरकारों को			42,03,56,000
(iv) श्रन्य बैंक	•	•		37,73,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	•		23,80,92,000
(ग) म्रन्य .		•		154,34,38,000	 (iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को (ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के वि राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) 			10,14,98,000
देग बिल	•	•	•	41,70,73,000	ग्रग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को व राष्ट्रीय ग्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकाली	हण और स्रप्रि	म .	14, 14, 37, 000
भ न्य देयताएं	•	•	٠	150,7 7 ,66,000	से ऋण, अग्रिम और निवेश (क) विकास बैंक को ऋण और धर्म (ख) विकास बैंक द्वारा जारी वि		f/	55,04,21,000
					डिबेंचरों में निवेश . यन्य ग्रस्तियां .			49,26,69,000
रु	पये	•		1146,07,14,000	रुपये			1146,07,14,000
** राष्ट्रीय कृषि @ राष्ट्रीय कृ	। ऋष्ण (दीर्व विऋण (दीर्व इंडिया ऋष्टि	कालीन वि वंकालीन	केयाएं) कियाएं)	निधि से प्रदत्त ऋण ग्रौ	गिक ऋज (दीर्घकालीन क्रियाएं) नि र स्रप्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य नुसूचित वाणिज्य देंकों को मीयादी वि	सरकारों के	प्रस्थायी	ं स्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

तारीख 21 जुलाई, 1971।

रिचर्च बैंक ग्राफ इंडिया ग्रिधिनियम, 1934 के ग्रनुसरण में जुलाई 1971 की 16 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इष्ट्र विभाग

देयताएं	रुप ये	रुपये	श्रास्तियां	रुपये	रुपये
ॉ र्किंग विभाग में रखे हुए	नोट 22,56,52,000		सोने का सिवका श्रौर बुलियन	· :	
संचलन में नोट	4425,97,29,000		(क) भारत में र खा हुग्रा .	182,53,11,000	
बारी किए गए कुल नोट		4448,53,81,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुमा		
•			विदेशी प्रतिभूतियां	243,42,00,000	
. •			्र जोड़		425,95,11,000
			रुपये का सिवका		39,64,38,000
· ·			भारत सरकार की रूपया प्रतिष	मूर्तियाँ	398 2 , 9 4, 32 . 000
			देशी विनिमय बिल ग्रौर		
			दूसरे वाणिज्य पत्न		
कुल दे यताएं	•	4448,53,81,000		कुल ग्रस्तियां	4448,53,81,000
					एस० जगत्नाथन,

तारीख 21 जुलाई, 1971।

्यं भगनायन, गर्वनर । [सं० एफ०३(३)-बी० सी०/71]

New Delhi, the 18th August 1971

S. O. 3397.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, 28 on the 13th August, 1971.

Banking Department

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	25,79,70,000 2,93,00 0
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,60,000
	2,0,000,000,000	Bills Purchased and Discounted:	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	190,00,00,000	(a) Internal	7,60,8 7,0 0
		(b) External	••
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	39,00,00,000	(c) Government Treesury Bills	42 ,93, 95, 00
		Balances Held Abroad*	144,07,70,00
		Investments**	289,25,73,00
		Loans and Advances to :-	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund .	135,00,00,000	(i) Central Government	157,88,07,00
Deposits :— '		Loans and Advances to :	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	104,91,15,00
(i) Central Government	5 1,73, 9 3,00 0	(ii) State Co-operative Banks††	211,91,33,000
(ii) State Governments	4,21,08,000	(iii) Others	3,62,14,000
(b) Banks 9		Loans, Advances and Investments from National Agri- cultural Credit (Long Term Operations) Fund— (a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	213,39,35,000	(i) State Governments	42,02,94,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	10,41,36,000	(ii) State Co-operative Banks	23,32,51,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	81,21,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	
(iv) Other Banks	30,92,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentur	
(c) Others	181,81,60,000	Loans and Advances from National Agricultural Credi (Stabilisation) Fund	t 10,14,98,000

Bills Payable .	, ,	•	•		•	•		40,49,16,c 0 0	(a) Loans and Advances to the Development Bank
Other Liabilities		•	٠	•	•	•	•	143,39,64,000	ment Bank Other Assets
	Rupee	\$	•	•				1165,58,25,000	Rupees

^{*}Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

Dated the 18th day of August, 1971.

^{**}Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, and the National Industrial Credit (Long Term

[@]Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State

[†]Includes Rs. 74,91,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act. ††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabi-

S. TAGANNATHAN, lisation) Fund. Governor.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 13th day of August, 1971.

otes held in the Banking Department . 25,79,70,000		
otes in circulation	Gold Coin and Bullion:— (a) Held in India 182 (b) Held outside India	2,53,11,000
otal Notes issued	Foreign Securities 22	3,42,00,000
	TOTAL · · ·	405,95,11,00
	Rupee Coin	42,14,89,00
	Government of India Rupee Securities Internal Bills of Exchange and other commercial paper	3942,95,21,0
TOTAL LIABILITIES 4391,05,21,000		4391,05,21,0

K. YESURATNAM, Under Secy.

[No. F. 3(3)-BC 71.]

वेंकिंग विभाग

मई दिल्ली, 18 ग्रगस्त, 1971

एस॰ ओ॰ 339 7.— 13 ग्रास्त,	1971 को	रिज़र्वे	बैंक	ग्राफ	इंण्डिया	के	बेकिंग	विभाग के कार्यकलाप व	हा विवरण

देयताएँ			रुपये	भ्रास्तियां			रुप रे
चुकता पूंजी			5,00,00,000	नोट	,		25,79,70,000
ष्रारक्षित निधि			150,00,00,000	रुपये का सिक्का			2,93,000
				छोटा सिक्का			3,60,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण				खरीदे स्रौर भुनाए गये बिल:			
(दीर्घकालीन क्रियाएँ) निष्ठि .	•	•	190,00,00,000				
ाष्ट्रीय कृषि ऋण				(क) देशी			7,60,87,00
(स्थिरीकरण) निधि .		•	39,00,00,000	(ख) विदेशी .	•	•	• •
				(ग) सरकारी खजाना दिल	•		42,93,95,00
ाष्ट्रीय ग्रौद्योगिक ऋण				विदेशों में रखा हुग्रा बकाया *	-		144,07,70,00
दीर्घकालीन क्रियाएं) नि धि			135,00,00,000	निवेश ^{**}			289,25,73,00
ामा राशियां :—				ऋण ऋौर भ्रग्रिम :			
क) सरकारी				(i) केन्द्रीय सरकार को			
(i) केन्द्रीय सरकार .			51,73,93,000	(ii) राज्य सरकारों को \dagger .			157,88,07,000
(ii) राज्य सरकारें .			4,21,08,000				
ख) बैंक				ऋण ग्रौर ग्रप्रिमः—			
(i) प्रदूस्चित बा णिज्य बें क	•		213,39,35,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य दैं कों को † †			1 04, 91, 15,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	•	•	10,41,36,000	(ii) राज्य सहकारी बेंको को			211,91,33,000
				(iii) दूसरों को .			3,62,14,000

	देयता	₹			रुपये	धास् ति याँ	*	स्ये
						राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि ऋण, प्रश्निम और निवेश (क) ऋन और प्रश्निम :	से	
(iii) गैर धनुर	चित रा	म्य सहका ^र	री बैंक		8 1, 2 1, 0 0 0	(i) राज्य सरकारों को	•	42,02,94,000
(iv) अपन्य बैंक	••	•		•	30,92,000	(ii) राज्य सहकारी बेंकों को . (iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को .	•	23,32,51,000
(ग) भ्रन्य					181,81,60,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्विरी करण) निधि से ऋ		
य दिल		•	•		4),49,16,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋष भौर भ्रामि राज्य सहकारी बैंकों को ऋष भौर भ्रामि राष्ट्रीय श्रौद्योगिक ऋण(दीर्घकालीन क्रियार्	τ.	13,71,56,000
न्य देयताएँ	•	•	• .	-	143,39,64,000	ऋण श्रमिम और निवेश (क) विकास बैंक को ऋ व शोर श्रमिम	-,	
						(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये मए बांडों/	डिबेंचरों में	निवेश
						श्रन्य ्रश्नास्तियां		33,24,88,000
				रुपये	1165,58,25,000		स्पये	1165,58,25,000

[@] राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कियाएँ) निधि भौर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदक्त ऋण भौर अग्रिम सामिल नहीं हैं।

तारीख: 18 श्रगस्त, 1971

एस॰ जगन्नाचन, गवर्नर ।

रिवर्व दैंक प्राफ इंग्डिया प्रधिनियम, 1934 के प्रनुसरण में प्रगस्त 1971 की 13 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इसु विमाग

देयताएं	रुपये	रूपये	ग्रस्तियां	रुप ये	स्पये
किंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का ग्रोर बुलिय		
नोट चलन में नोट	25,79,70,000 4365,25,51,000		(क) भारत में रखा हुन्रा (ख) भारत के बाहर रखा	182,53,11,000	
			हुमा विदेशी प्रतिभूतियां	223,42,00,000	
ारी किए गये कुल नोट		4391,05,21,000			_
			बोड़	•	405,95,11,000
			रूपये का सिक्का .		42,14,89,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिष	वृतियाँ	3942,95,21,000
			देश्री विनिमय बिल ग्रौर दूसरे	े वाणिज्य पत्न	
कुल देयताएं	•	4391,05,21,000		कुत्त म्रास्तियां	4391,05,21,000

सं० एफ० 3 (3)-बी० सी०/71] के० येसूरत्नम, ग्रनु-सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 24th August 1971

S.O. 3398.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the 'prescribed authority' for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act 1961:

Institution

Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research, Bombay.

[No. 252/F. No. 203/17/71-IT(AII),]

S. N. NAUTIAL, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

ग्रायकर

नई दिल्ली, 24 श्रास्त, 1971

एसः क्रो॰ 3398.—-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न- वर्णित संस्था, भारतीय चिकित्सा श्रनुसंधान परिषद् द्वारा, जो विहित प्राधिकारी है, श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, श्रमुमोदित की गई है।

संस्था

सोसाइटी फार रिकन्स्ट्रिक्टिय सर्जरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च, मुम्बई।
[सं० 252 (फा० सं० 203/17/71-म्रा० फ०(ए II)]
एस० एन० नौटियाल. उप सचित्र।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 11th September 1971

S.O. 3399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 72-Customs, dated the 16th August, 1971, namely:—

In the said notification, for the words "when wholly produced in Nepal and imported into India", the words "memufactured in Nepal and containing not less than ninety per cent of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials and when imported into India" shall be substituted.

[No. 82-Customs/F. No. 552/183/71-LCI.]

(राजस्व ग्रौर बीमा विभाग)

सीमा-शस्क

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 1971

एस॰झो॰ 3399.—सीमा-शुल्क प्रधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना श्रावश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व श्रीर बीमा विभाग) की प्रधिसूचना सं० 72—सीमा-शृहक, तारीख 16 श्रगस्त, 1971, में एतव्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , श्रर्थात् :---

उक्त अनुसूची में में " अब कि वे पूर्णतः नेपाल में उत्पादित किए गए हों और नेपाल से भारत में आयात किए गए हों" शब्दों के स्थान पर "नेपाल में विनिर्मित किए गए हों, और जिस में 90 प्रतिशत से भन्यून नेपाली सामग्री या नेपाली और भारतीय व सामग्री हों और जब नेपाल से भारत में आयात किए गए हों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ 82-सीमा-शुल्क/फा॰ सं॰ 552/183/71-एल॰सी॰माई॰]

ORDER

STAMPS

New Delhi, the 11th September 1971

S.O. 3400.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds of the face value of fifty-five lakes of rupees, to be issued by the Kerala Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 20/71-Stamps/F. No. 471/33/71-Cus. VH(.)]

K. SANKARARAMAN, Under Secy.

भ्रादेश

स्टाम्प

नई दिल्ली 11, सितम्बर, 1971

एस॰ म्रो॰ 3400--भारतीय स्टाम्प श्रिधिनियम, 1899 (1899का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उस शुल्क से, जिसके द्वारा केरल फाइनेशियल कारपोरेशन द्वाराजारी किए जाने वाले पचपन लाखरूपए के ग्रीकित मूल्य के बंध पन्न उस श्रिधिनियम के श्रिधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 20/71-स्टाम्प/फा०सं० 471/33/71-सी० गु०]

के० शंकररमन, भवर समिव।

